सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
YouTube

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 01, अंक 17, नई दिल्ली | शनिवार, 02 अप्रैल 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

आज का सुविचार

बुरा वक्त भी हमे कुछ नया सीखा जाता है, कुछ नया नहीं तो, हमे अपने और पराये की पहचान करा ही जाता है।

इनसाइड

दो दिन से नहीं दौड़ रहीं इलेक्ट्रिक बसें, 50 हजार यात्री बे'बस'

मेरठ। मेरठ में चार्जिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक फाल्ट के कारण शहर भर की 50 इलेक्ट्रिक बसें डिपो में खड़ी हैं। ऐसे में 50 हजार से भी ज्यादा यात्री बेबस नजर आ रहे हैं। अधिकारियों ने आज फाल्ट ठीक होने की संभावना जताई है। इलेक्ट्रिक फाल्ट के चलते पिछले दो दिनों से मेरठ शहर और देहात की इलेक्ट्रिक बस सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। सभी 50 इलेक्ट्रिक बसें डिपो में खड़ी हैं। अभी तक फाल्ट ठीक नहीं हो पाया है, जिस कारण मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट को दो दिन में सात लाख रुपये से अधिक का नुकसान हो गया है। बसें न चलने से 50 हजार से अधिक यात्री परेशान हैं। बुधवार को लोहिया नगर स्थित इलेक्ट्रिक बस डिपो के एलटी पैनल में फाल्ट हो गया था। फाल्ट को ठीक करने के लिए वीएसके सिटी बस ऑपरेटर प्रा. लि. कंपनी के कर्मचारी ने प्रयास किया तो वहां धमाका हो गया। इसमें कर्मचारी भी झुलस गया था।

दिल्ली में लापरवाही से बे'बस' हुए लाखों लोग

जांच कंपनी नहीं दे सकी नत्थू फ्लाईओवर की फाइनल रिपोर्ट

दिल्ली की नत्थू कॉलोनी स्थित फ्लाईओवर पर निर्माण कार्य में आई खामी की जांच कर रही कंपनी ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है जिसके कारण साल 2015 से अभी तक इसके निर्माण में आई कमियों के लिए जिम्मेदारों का पता नहीं चल सका है।

संजय बाटला

नई दिल्ली। करीब आठ साल पहले बसों व भारी वाहनों के लिए बंद किया गया नत्थू कालोनी फ्लाईओवर पर अभी भी हल्के वाहन ही दौड़ सकेंगे। लाखों लोग इससे परेशान हो रहे हैं। साल 2015 से अभी तक इसके निर्माण में आई खामी के लिए जिम्मेदारों का पता नहीं चल सका है। जो तकनीकी कंपनी इसकी मजबूती की जांच कर रही है, वह फाइनल रिपोर्ट नहीं दे सकी है।

बताया जा रहा है कि इसकी मजबूती जांचने के लिए अभी कुछ टेस्ट बाकी हैं। 2013 में बने फ्लाईओवर के लोड बेयरिंग टेस्ट के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआइआइ) से तकनीकी रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के बाद भारी वाहनों के दौड़ने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

लाखों लोग परेशान

नंद नगरी, मानसरोवर पार्क, अशोक नगर, चंद्रलोक, नत्थू कालोनी, छज्जुपुर, कर्दम पुरी समेत करीब दो दर्जन से अधिक कालोनियों के लाखों लोग फ्लाईओवर पर बसें न चलने से परेशान हैं। दरअसल, पहले सीमापुरी और नंद नगरी डिपो से चलने वाली ज्यादातर बसें इसी फ्लाईओवर से होकर गुजरती थीं।

रोका गया सात करोड़ का भुगतान

पिछले दिनों विधायक जितेंद्र महाजन ने विधानसभा में सवाल उठाया तो जवाब मिला कि फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी गैमन इंडिया का 7.49 करोड़ का भुगवान रोका गया है। जन कल्याण मंच के अध्यक्ष वेद पाल सिंह प्रेमी बसों के संचालन के लिए सरकार को कई पत्र लिख चुके हैं। हालांकि कोई लाभ नहीं हुआ।

ना किसी के दबाव में, ना किसी के प्रभाव में !!!
निर्भकता से आपके लिए प्रस्तुत करे खबरे
सिर्फ और सिर्फ, सच :- परिवहन विशेष

अब आपके लिए अवसर परिवहन विशेष समाचार पत्र मे काम करने का

अगर आप को पत्रकारिता का शौक है और जनहित के मुद्दों को लिखने/उठाने और उनका हल करवाने के इच्छुक है तो आप परिवहन विशेष (हिन्दी दैनिक) समाचार पत्र के साथ जुड़कर अपना सपना/इच्छा पूरी कर सकते हैं।

इस फेलोशिप के जरिए आपको मिलेगा पत्रकारिता में सफलता प्राप्त कर पत्रकार बनने के अवसर । फेलोशिप के दौरान आप देश के हिन्दी अखबार दैनिक के साथ काम कर पाएंगे। 15 माह की फेलोशिप पूरी करने के बाद आपके पास होगा परिवहन विशेष में नौकरी करने का अवसर ।

जर्नलिजम प्रिंट एवं डिजिटल फेलोशिप

फेलोशिप के दौरान दूसरे माह से कार्य करने के प्रति जागरूकता और क्षमता के अनुसार मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा।

जरूरी योग्यता :-हिन्दी बोलने, पढ़ने और लिखने में दक्षता।

आवेदन 25 मार्च 2023 से 30 अप्रैल 2023 के बीच किए जा सकते हैं।

newstransportvishesh@gmail.com
www.newstransportvishesh.com

भारी माल, यात्री वाहनों को राहत, अनिवार्य फिटनेस टेस्टिंग की तारीख इतने समय के लिए बढ़ाई गई

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अब, देश भर में ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशनों (ATS) की तैयारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए MoRTH ने लिया ये फैसला

परिवहन विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। सरकार ने भारी माल वाहनों और पैसेंजर मोटर वाहनों के लिए एक पंजीकृत ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) के जरिए अनिवार्य फिटनेस टेस्टिंग की तारीख को 18 महीने बढ़ाकर 1 अक्तूबर, 2024 कर दी है।

इससे पहले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा था कि एटीएस के जरिए भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण 1 अप्रैल, 2023 से अनिवार्य होगा।

हालांकि, मध्यम माल वाहनों, मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के मामले में, MoRTH ने कहा था कि यह आवश्यकता 1 जून, 2024 से अनिवार्य कर दी जाएगी।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अब, देश भर में ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशनों (ATS) की तैयारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, MoRTH ने भारी माल वाहनों / भारी यात्री मोटर वाहनों, मध्यम माल वाहनों / मध्यम यात्री मोटर वाहन और हल्के मोटर वाहन (परिवहन) के संबंध में ATS के जरिए अनिवार्य परीक्षण की तारीख को 1 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है।

एक ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) वाहन की फिटनेस की जांच के लिए जरूरी विभिन्न परीक्षणों को स्वचालित करने के लिए मैकेनिकल उपकरण का इस्तेमाल करता है।

मंत्रालय ने 2021 में कहा था कि स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, राज्य सरकारों, कंपनियों, संघों और व्यक्तियों के निकायों को व्यक्तिगत और परिवहन दोनों वाहनों की फिटनेस के परीक्षण के लिए एटीएस खोलने की अनुमति दी जा सकती है। व्यक्तिगत वाहनों (गैर-परिवहन) के लिए फिटनेस परीक्षण पंजीकरण के नवीनीकरण के समय (15 वर्ष के बाद) किया जाता है।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्ली मेट्रो में जनरल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पदों पर भर्ती, 3 लाख तक मिलेगी सैलरी

परिवहन विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) लिमिटेड ने जनरल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पदों पर भर्ती निकाली है। डीएमआरसी की इस भर्ती (DMRC Recruitment 2023) के लिए जो भी उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर कर Executive Director (HR) Delhi Metro Rail Corporation Ltd, Metro Bhawan, Fire Brigade Lane, Barakhamba Road, New Delhi पर भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार जनरल मैनेजर पदों पर भर्ती (DMRC Bharti 2023) के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 18 अप्रैल तक फॉर्म जमा करना होगा वहीं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को 17 अप्रैल तक अपना फॉर्म भेजना होगा।

महत्वपूर्ण तारीख

जनरल मैनेजर पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 18 अप्रैल तक एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दें और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को 17 अप्रैल तक अपना फॉर्म भेजना होगा।

शैक्षिक योग्यता

जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उनके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार शैक्षिक योग्यता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर भर्ती का नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें।

उम्र सीमा

जनरल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी उम्र 59 वर्ष है। उम्र सीमा के विषय में अधिक जानकारी के लिए भर्ती से पहले नोटिफिकेशन पढ़ लें।

सैलरी

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की इस भर्ती में मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए चयनित होने के बाद सैलरी के रूप में 1,20,000 रुपये से लेकर 2,80,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 3,00,000 रुपये सैलरी के रूप में मिलेंगे।

दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद जब तक आग पर काबू पाया तब तक बस जलकर स्वाह हो चुकी थी.

बड़ा हादसा : दिल्ली-देहरादून हाईवे पर चलती लग्जरी बस में लगी आग, सवार थे विदेशी सहित 31 यात्री

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर शनिवार की दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब देहरादून से दिल्ली की ओर जा रही एक डबल डेकर बस में अचानक से भीषण आग लग गई. अगलगी की इस घटना में किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं है.

परिवहन विशेष न्यूज

मुजफ्फरनगर. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर शनिवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब देहरादून से दिल्ली की ओर जा रही एक डबल डेकर बस में अचानक से भीषण आग लग गई. घटना के बाद जहां किसी तरह बस में सवार सवारियों ने बस से कूद कर अपनी जान बचाई तो वहीं सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद जब तक आग पर काबू पाया तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी.

दरअसल नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर शनिवार को देहरादून से चलकर दिल्ली जा रही एक डबल डेकर चलती बस में अचानक से आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया जिसके चलते हाईवे पर हड़कंप मच गया. बस में सवार तकरीबन 31 सवारियों ने किसी तरह बस से कूदकर अपनी जान बचाई. घटना की सूचना पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद जब तक आग पर काबू पाया तब तक बस जलकर स्वाह हो चुकी थी.

आग लगने के सही कारणों का तो अभी पता नहीं लग पाया है लेकिन बताया जा रहा है इस बस में 31 सवारियां सवार थी जिनमें एक विदेशी नागरिक भी था. ये बस इन सवारियों को लेकर देहरादून से चलकर दिल्ली की ओर जा रही थी. इस घटना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बस के कंडेक्टर अजित ने बताया कि बस देहरादून से दिल्ली जा रही थी. इसी दौरान अचानक ही एकदम गाड़ी में थोड़ी सी आवाज आती है. एकदम पीछे हम गए तो अचानक ही गाड़ी में आग लग गई.

जिस वक्त बस में आग लगी उस वक्त उसमें 31 लोग सवार थे. एक विदेशी पैसेंजर भी था जो देहरादून से आया. घटना की जानकारी देते हुए एफएसओ मुजफ्फरनगर आर के यादव ने बताया कि बस में आग लगी थी. गाड़ी को तुरंत रोक कर सवारियों को जल्द बाहर निकाल दिया गया. उनका सामान भी सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, कोई जनहानि नहीं है कोई हताहत नहीं है. यह गाड़ी देहरादून से दिल्ली की ओर जा रही थी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिछले टायर में आग लगने का मतलब हो सकता है या तो कोई घिसाव होगा, या टेंपरेचर से आग लगी होगी.

इनसाइड

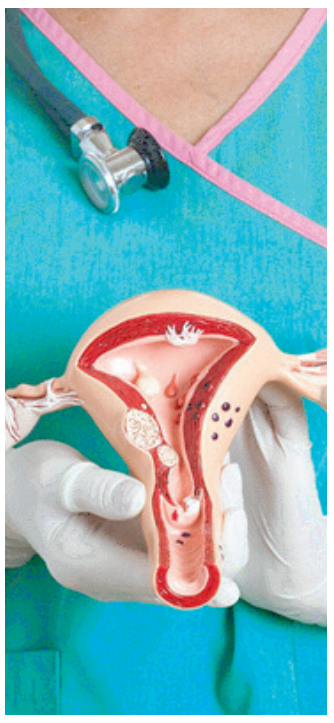

सर्वाइकल कैंसर का खतरा युवा महिलाओं को ज्यादा, अपोलो की डॉक्टर सारिका गुप्ता ने बताए बचाव के तरीके

कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि की वजह से हो जाता है. कैंसर कई तरह के होते हैं. इनमें से एक सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) होता है, जो महिलाओं में होने वाला कॉमन कैंसर है. दुनियाभर में हर साल बड़ी तादाद में महिलाएं महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं. चिंताजनक बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम उम्र की महिलाओं को ज्यादा होता है. आज कैंसर स्पेशलिस्ट से जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है.

नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी ओन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सारिका गुप्ता के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर महिलाओं की बच्चेदानी के मुख में होने वाला कैंसर है. इसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है. आमतौर पर 35 साल से लेकर 50 साल की उम्र वाली महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का खतरा ज्यादा होता है. यह कैंसर दो तरह का होता है- पहला लो ग्रेड और दूसरा हाई ग्रेड. लो ग्रेड कैंसर धीरे-धीरे फैलता है, जबकि हाई ग्रेड कैंसर तेजी से फैलता है और इसमें मौत का खतरा ज्यादा होता है. ऐसे में सही वक्त पर इलाज कराना बेहद जरूरी है.

ऐसी महिलाओं को खतरा ज्यादा

डॉक्टर सारिका गुप्ता कहती हैं कि सर्वाइकल कैंसर का खतरा उन महिलाओं को ज्यादा होता है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो और एचआईवी या अन्य कोई गंभीर बीमारी हो. मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जेनिटल हाइजीन की कमी और जल्दी बच्चे होने वाली महिलाओं को इसका जोखिम ज्यादा होता है. इसके अलावा स्मोकिंग करने से भी सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. 30 साल की उम्र के बाद महिलाओं को इससे बचने के लिए समय-समय पर स्क्रीनिंग करानी चाहिए. सर्वाइकल कैंसर का पता प्री-कैंसरस स्टेज में भी लगाया जा सकता है और सही इलाज के जरिए कैंसर से बचा भी जा सकता है.

सर्वाइकल कैंसर के लक्षण

– पार्टनर के साथ संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग
– पीरियड्स के बीच अनियमित माहवारी होना
– बदबूदार पानी आना या ब्लड स्ट्रीम डिस्चार्ज
– मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना

सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट और बचाव

डॉक्टर के अनुसार सर्वाइकल कैंसर अगर शुरुआती स्टेज में हो, तो सर्जरी के जरिए इसका इलाज किया जाता है. एडवांस स्टेज में कीमोथेरेपी की जरूरत होती है. हर मरीज की कंडीशन को देखकर ही ट्रीटमेंट किया जाता है. जितना जल्दी इसका पता लग जाए, मौत का खतरा उतना कम हो सकता है. बचाव की बात करें, तो सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए HPV का टीका लगवाएं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें. स्मोकिंग से दूरी बनाएं और संबंध बनाते वक्त कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करें. समय-समय पर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी जांच करवाएं.

महिलाओं में 5 लक्षण दिखें तो हो जाएं अलर्ट

खराब मेंटल हेल्थ के होते हैं संकेत, सही वक्त पर करें सेल्फ

अत्यधिक अपराधबोध, भय, शर्म या क्रोध का होना भी मेंटल प्रॉब्लम के शुरुआती लक्षण हैं.अत्यधिक अपराधबोध, भय, शर्म या क्रोध का होना भी मेंटल प्रॉब्लम के शुरुआती लक्षण हैं.डिप्रेशन और एंग्जायटी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है. ये दिमागी बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. हकीकत यह है कि महिलाएं महीनों, सालों और कई बार तो जीवनभर इस परेशानी से जूझती हैं, जो बाद में और भी परेशानी की वजह बन जाते हैं. आज आपको बता रहे हैं कि महिलाओं में मेंटल हेल्थ के खराब होने के शुरुआती लक्षण क्या हैं.

अक्सर यह देखने को मिलता है कि महिलाएं अपने मेंटल हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं होतीं और सालों साल डिप्रेशन और एंग्जायटी की समस्या से जूझती रहती हैं. इलाज के अभाव में समस्या और भी बढ़ जाती है और हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं. आज के बिजी लाइफ स्टाइल में महिलाएं घर और दफ्तर दोनों को सम्हालती हैं और मेंटल हेल्थ से जुड़ी काफी मामलों को नजरअंदाज कर देती हैं. लेकिन अन्य बीमारियों की तरह यह समस्या भी रुकती नहीं और धीरे धीरे जीवन को कई तरह से प्रभावित करती चली जाती हैं. आइए जानते हैं कि महिलाओं में मेंटल हेल्थ की समस्या के शुरुआती लक्षण क्या हैं.

जीवन में कठिनाइयां बढ़ना- क्लीयरव्यू ट्रीटमेंट प्रोग्राम के मुताबिक कभी-कभी मानसिक बीमारी के पहले लक्षण के रूप में देखा जाता है कि महिलाओं का परफॉरमेंस एकाएक खराब होने लगता है. मसलन, खराब ग्रेड आना, काम अच्छा ना होना, अच्छी तरह से जिम्मेदारियों को ना निभा पाना, स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाना, पर्सनल रिलेशन में समस्या आदि. ऐसे लक्षण महिलाओं में मेंटल हेल्थ के बिगड़ने के लक्षण हो सकते हैं.

मूड और भावनाओं में बदलाव- अगर अचानक से महिला के मूड में परिवर्तन हो या मूड में उतार-चढ़ाव आए तो ये भी मानसिक बीमारियों का एक और प्राथमिक संकेत हो सकता है. मसलन, उदास रहना, उत्साह की कमी, एनर्जी और भावनाओं की कमी या उदासीनता की भावना आदि. यही नहीं, ऐसी अवस्था में अत्यधिक अपराधबोध, भय, शर्म या क्रोध का अनुभव भी कर सकता है.

संज्ञानात्मकता की कमी- संज्ञानात्मकता की कमी यानी कि चीजों को बार बार भूलना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई या भ्रम होना आदि लक्षण मानसिक बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. ऐसे हालत में इंसान इंसानों को भूल सकता है और वह कहीं खोया खोया रहता है.

खतरनाक व्यवहार- मानसिक बीमारी अगर अपने शुरुआती दौर में है तो कभी-कभी ऐसी महिलाएं जोखिम भरे व्यवहार करने लगती हैं. मसलन, अत्यधिक मात्रा में पैसा खर्च करना, जोखिम भरा यौन व्यवहार करना या ड्रग्स और शराब के साथ प्रयोग करना. इस परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए कई बार लोग ड्रग्स या शराब की लत तक के शिकार हो जाते हैं.

हकीकत से दूर होना- कई बार महिलाएं तनाव झेलते झेलते मतिभ्रम महसूस करने लगती हैं जिसमें उन्हें लगता है कि कुछ हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. ऐसा लक्षण होने पर तुरंत आप साइक्रेटिस्ट से संपर्क करें और विशेषज्ञों से मदद लें.

लक्षण दिखने कर क्या करें?

–अगर आप कुछ ऐसा अनुभव कर ही हैं तो विशेषज्ञ की सलाह लें.
–योग और ध्यान का सहाला लें और वॉकिंग या जॉगिंग करें.
–लोगों से मिलें और क्लब आदि ज्वाइन करें.
–बिहेवियर थेरेपी की मदद लें.

प्रियंका चोपड़ा ने 30 की उम्र में अपने एग कराए थे फ्रीज़, आखिर क्यों प्रचलित हो रहा यह तरीका

बॉलीवुड में एग फ्रीजिंग तकनीक काफी फेमस हो रही है. हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने भी इस तकनीक की मदद से बच्ची को जन्म दिया है. आखिर ये तकनीक क्यों फेमस हो रही है और फैमिली प्लानिंग में ये किस तरह लोगों की मदद कर रही है, इस बारे में सभी को कुछ बातें जान लेनी चाहिए.

प्रियंका चोपड़ा हाल ही में जाने माने अमेरिकन एक्टर फिल्ममेकर डैक्स शेफर्ड के पॉडकास्ट आर्मचेयर एक्सपर्ट के शो में अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ जरूरी फैसलों पर चर्चा करते हुए कई बातों को खुलासा किया. इस मौके पर उन्होंने खुलकर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने अपनी मां की सलाह पर अपने एग्स फ्रीज करवाए थे. उन्होंने बताया कि अपने 30 वें साल में लिए गए इस निर्णय की वजह से उन्हें जीवन में कई आजादी भी मिली. प्रियंका अभी 40 साल की हैं और सिंगर एक्टर निक जोनस के साथ एक खुशहाल मैरिड लाइफ जी रही हैं. हाल ही में एग फ्रीजिंग तकनीक से उन्हें बेटी भी हुई है, जिसका नाम मालती मेरी चोपड़ा जोनस है.

आखिर क्या है एग फ्रीजिंग?

मेडिकल न्यूज टुडे के मुताबिक, एग फ्रीजिंग एक मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें एक महिला के पास यह विकल्प होता है कि वह बच्चे पैदा करने की उम्र निकल जाने के बाद भी सेरोगेसी से अपने बच्चे को जन्म दे सकती है. दरअसल, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, महिलाओं में अंडे की क्वालिटी घटती जाती है. ऐसे में महिला बच्चे को जन्म तो देना चाहती है लेकिन सिचुएशन की वजह से फिलहाल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो ऐसी महिलाओं के लिए एग फ्रीजिंग तकनीक काफी सुविधाजनक और सेफ विकल्प हो सकता है.

एक फ्रीजिंग का क्यों बढ़ रहा ट्रेंड?

करियर और एजुकेशन प्लान में सुविधा- जो महिलाएं एडवांस या हाइयर एजुकेशन में डिग्री हासिल करना चाहती हैं या करियर की वजह से उन्हें प्रेग्नेंसी के लिए मौका नहीं मिल पा रहा, ऐसी महिलाएं युवा अवस्था में अपने भविष्य के प्लान के लिए अंडे फ्रीज करवा सकती हैं. ऐसा करने से महिलाओं के पास एक आजादी होती है कि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, अच्छा करियर बना सकें और उम्र होने पर अपना परिवार भी बढ़ा सकें.

व्यक्तिगत परिस्थितियां- जो महिलाएं बच्चे तो पैदा करना चाहती हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई परफेक्ट साथी नहीं मिला है तो वे भविष्य में उपयोग के लिए अपने अंडे को फ्रीज करा सकती हैं. समलैंगिक संबंधों में रहने वाली महिलाएं भी बाद में बच्चा पैदा करने की इच्छा होने पर ऐसा कर सकती हैं.

कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए विकल्प- अगर महिला कैंसर पीड़ित है तो कीमोथेरेपी और अन्य कैंसर उपचार में आमतौर पर प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और कई बार तो प्रजनन क्षमता खत्म भी हो जाती है. ऐसे में महिला पहले ही अपने एग को फ्रीज करा सकती हैं और इलाज के बाद फैमिली प्लानिंग कर सकती हैं.

6 बदलाव, जो 40 की उम्र के बाद हर महिला झेलती है! नॉर्मल हैं ये मेंटल और फिजिकल चेंज

इस उम्र में कई शारीरिक व मानसिक बदलाव

उम्र बढ़ने के साथ ही महिलाओं के मानसिक और शारीरिक सेहत में कई बदलाव तेजी से देखने को मिलते हैं. ये बदलाव कई बार फ्रस्टेटिंग होते हैं तो कई बार दैनिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि 40 की उम्र के बाद किस तरह के बदलाव महिलाएं महसूस करती हैं.

उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है. लेकिन जब महिलाएं 40 की उम्र में प्रवेश करती हैं तो उनके शारीरिक और मानसिक सेहत में कुछ ऐसे बदलाव आने शुरू होते हैं जिसे वह आसानी से महसूस कर पाती है और लगभग हर महिला ऐसी समस्याओं से जूझती है. कुछ महिलाएं ऐसे बदलाव से इरिटेट होने लगती हैं और कुछ निराश हताश. यह वह समय होता है जब मेनोपॉज की तरफ आप बढ़ना शुरू करती हैं. इस समय महिलाएं शारीरिक और मानसिक बदलावों की वजह से निराश और कई बार अनकंफर्टेबल भी महसूस करती हैं. लेकिन आपको बता दें इनका समाधान संभव है.

प्रिवेंट वेबसाइट में इन विषयों की एक्सपर्ट पीएचडी, लॉरा बरमन का कहना है कि महिलाएं ऐसे हालातों को चुपचाप सहती हैं जबकि उन्हें अपने डॉक्टर से इस विषय पर सलाह लेने की जरूरत होती है. यहां हम आपको बताते हैं कि 40 की उम्र के बाद किस तरह के बदलावों से महिलाएं गुजरती हैं.

40 की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में बदलाव

ब्रेन फॉगिंग

अगर आप चीजों को रखकर भूल जा रही हैं या आप छोटी-छोटी बातों को याद नहीं रख पा रहीं तो ये ब्रेन फॉगिंग का लक्षण हो सकता है. ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और सही सलाह लें.

ब्लडर लीक होना

अगर आप महसूस करती हैं कि छींकने या खांसने आदि से ब्लडर से कंट्रोल छूट रहा है और लीक हो रहा है तो यह समस्या भी आपके लिए मुसीबत बन सकती है. 40 प्रतिशत महिलाएं 40 की उम्र के बाद ऐसी समस्याओं से जूझती हैं.

बालों का झड़ना

बालों के झड़ने की समस्या भी ज्यादातर महिलाएं 40 की उम्र के बाद महसूस करती हैं. यह हार्मोनल बदलाव की वजह से हो सकता है. अगर आपके बाद काफी झड़ रहे हैं तो आप डर्मोटोलोजिस्ट से संपर्क करें.

फेशियल हेयर का बढ़ना

उम्र बढ़ने पर महिला के शरीर में एस्ट्रोजन लेवल कम होता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है. इसकी वजह से चेहरे, ठोरी, उंगलियों आदि पर बाल नजर आने लगते हैं.

सफेद बाल होना

उम्र बढ़ने के साथ ही सिर के बाल ग्रे नजर आने लगते हैं.यही नहीं, शरीर के अन्य हिस्सों पर मौजूद बालों में भी सफेद बाल नजर आने लगते हैं. इसकी वजह से कई महिलाएं शर्म महसूस करने लगती हैं. जबकि यह बॉडी को बिलकुल नॉर्मल प्रोसेस है.

हॉट फ्लश अनुभव करना

80 प्रतिशत महिलाएं मेनोपॉज के वक्त हॉट फ्लश अनुभव करती हैं. यह सिलसिला 7 से 10 साल तक चल सकता है. हालांकि यह समस्या ब्लड क्लॉट, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं.

व्हट्सअप चैट करने में महिलाएं पुरुषों से आगे, सर्वे में खुलासा, मेंटल हेल्थ से जुड़ा है मामला

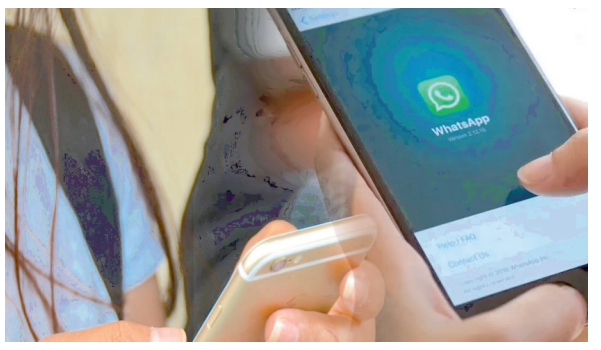

व्हाट्सएप पर चैट करने में महिलाएं पुरुषों से काफी आगे हैं. हाल ही में मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन (Mental Health Helpline) की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि टेलिफोन पर कंसल्टेशन या काउंसलिंग लेने के बजाय महिलाएं व्हाट्सएप चैट (WhatsApp Chat) के माध्यम से गोपनीय तरीके से मदद लेना पसंद करती हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स फेसबुक (Facebook), ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलिग्राम, व्हाट्सएप (WhatsApp) या अन्य किसी भी एप्लिकेशन का इस्तेमाल आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है. चाहे किसी समस्या का समाधान ढूंढना हो, मनोरंजन करना हो, जानकारी लेनी-देनी हो या सगे-संबंधियों से बातचीत करनी हो तो लोग इन एप्स (App) का इस्तेमाल करते हैं. कभी-कभी चैट में मैसेज टाइप करते-करते उलझन सी भी महसूस की होगी लेकिन महिलाओं के मामले में ऐसा नहीं है. व्हाट्सएप पर चैट करना (WhatsApp Chatting) महिलाओं को न केवल फोन पर बात करने के मुकाबले ज्यादा आसान लगता है बल्कि कॉन्फिडेंशियल भी लगता है. वे व्हाट्सएप चैट करने में पुरुषों से काफी आगे हैं. खास बात है कि ये चैट भी इस हेल्पलाइन 9999666555 नंबर पर की गई है जो एक मेंटल हेल्थ ऑर्गनाइजेशन का है.

मानसिक स्वास्थ्य संगठन वंद्रेवाला फाउंडेशन की फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन के 3 महीनों के आंकड़े बताते हैं कि फाउंडेशन की हेल्पलाइन पर मेंटल इश्यूज को लेकर सलाह और परामर्श लेने वालों में युवा आबादी ने सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का उपयोग किया है. जबकि मध्यम आयु वर्ग और उससे ऊपर के लोगों ने टेलीफोनिक बातचीत को अधिक पसंद किया.

आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश युवा अपने मानसिक स्वास्थ्य की मदद के लिए व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं और इसे बेहतर मानते हैं. 18 वर्ष से कम आयु के 65 फीसदी, 18-35 आयु वर्ग के 50 फीसदी, 35-60 आयु वर्ग के 28.3% और 60 वर्ष से अधिक आयु के 8 फीसदी लोगों ने मेंटल हेल्थ के लिए व्हाट्सएप यूज किया है.

53 फीसदी महिलाएं जबकि पुरुष 42 फीसदी..

फाउंडेशन के डेटा के अनुसार लगभग 53 फीसदी महिलाएं व्हाट्सएप चैट का उपयोग करके हेल्पलाइन से संपर्क करना पसंद करती हैं, जबकि 42 फीसदी पुरुष व्हाट्सएप चैट का उपयोग करना पसंद करते हैं. वहीं बाकी मामलों में लोग टेलिफोन के द्वारा काउंसलिंग लेते हैं.

खास बात है कि व्हाट्सएप ने उस वर्ग को सबसे ज्यादा राहत दी है जो शायद कभी भी मानसिक स्वास्थ्य सहायता ऑफलाइन क्लीनिकों पर जाकर नहीं ले सकता था. खासतौर पर ऐसी महिलाएं, लड़कियां और युवक जो अपने परिवार या साथियों को बिना बताए अपने मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं पर चर्चा करना चाहते हैं वे व्हाट्सएप का इसके लिए इस्तेमाल करते हैं. वे इसे गोपनीय मानते हैं और समय की उपलब्धता के अनुसार साइलेंट तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान हासिल कर पाते हैं.

सुसाइड के विचारों से जूझ रहे लोग

फाउंडेशन की प्रमुख और परोपकारी, प्रिया हीरानंदानी वंद्रेवाला कहती हैं, 'हमसे संपर्क करने वाले एक तिहाई लोगों ने हमें बताया कि वे मानसिक बीमारी, चिंता, अवसाद और आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं.

राहुल गांधी के नाम किया इस महिला ने अपना चार मंजिला मकान....

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद उन्हें सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। नियम के मुताबिक अयोग्य ठहराये गए सदस्य को एक महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होता है। वहीं दिल्ली की एक महिला ने अपना एक चार मंजिला मकान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के नाम किया है।

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद दिल्ली की एक महिला ने अपना चार मंजिला मकान राहुल गांधी के नाम किया है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में राजकुमारी गुप्ता ने 4 मंजिला मकान राहुल गांधी के नाम किया है। राजकुमारी गुप्ता दिल्ली कांग्रेस सेवा दल से जुड़ी हैं। लोकसभा की सदस्यता (Lok Sabha Membership) से अयोग्य घोषित कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक उन्हें सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस मुहिम चलाई थी मेरा घर राहुल गांधी का घर। राहुल गांधी को पिछले सप्ताह लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के मद्देनजर लोकसभा की आवास संबंधी समिति ने कांग्रेस नेता को 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने के लिये नोटिस भेजा है।

गुजरात में सूरत की एक अदालत ने 'मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें 23 मार्च को दोषी ठहराया तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया। अयोग्य ठहराये गए सदस्य को उनकी सदस्यता जाने के एक महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होता है।

रेड लाइट जंप कर रहा था मर्सिडीज वाला, रोकने पहुंचे कॉन्स्टेबल को पहली गाली दी फिर पीट डाला

दिल्ली में बीच सड़क पर पुलिस कॉन्स्टेबल को पीटने का मामला सामने आया है। घटना सेंट्रल दिल्ली के तुगलक रोड के पास की है। यहां रेड लाइट जंप कर रहे कार सवार ने ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रोके जाने पर आपा खो दिया। इसके बाद उसने कार से उतर पहले गालियां दी फिर कॉन्स्टेबल को पीट दिया।

नई दिल्ली : सेंट्रल दिल्ली के तुगलक रोड पर लाल बत्ती पार करने के कारण रोके गए मर्सिडीज चालक ने पुलिस कांस्टेबल को कथित रूप से गालियां दी और उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने शनिवार को बताया कि कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की उम्र 28 से 30 साल के बीच है और उसका दावा है कि उसके पिता केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सहायक उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार और कांस्टेबल सुरेंद्र की 25 मार्च को हुमायूं रोड पर सुब्रमण्यम भारती मार्ग टी-पॉइंट पर ड्यूटी थी।

कार से उतरते ही देने लगा गालियां

प्राथमिकी के अनुसार, शाम 6 बजकर करीब 55 मिनट पर सफेद मर्सिडीज और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार लाल बत्ती पार कर हुमायूं रोड पर आ गए। तब सिंह ने कुमार को वाहनों को रोकने का निर्देश दिया। प्राथमिकी में बताया गया कि जैसे ही कार रूकी, मर्सिडीज चालक (जिस पर एक अस्थायी नंबर प्लेट लगी थी) कार से उतरा और कथित रूप से कुमार को गालियां दीं और उसके साथ मारपीट भी की। इस दौरान फॉर्च्यूनर में सवार आरोपी के निजी सुरक्षा कर्मी ने उसे समझाने की कोशिश की।

मेरे पापा होम मिनिस्ट्री थे

प्राथमिकी में कहा गया है कि मर्सिडीज चालक ने फिर दावा किया कि उसके पिता गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे और कुमार को चेतावनी दी थी कि उनकी कार्रवाई से उनकी नौकरी प्रभावित हो सकती है। पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार को तुगलक रोड थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (सरकारी कर्मचारी के सरकारी काम में बाधा डालना), धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकने के लिए उसके खिलाफ बल प्रयोग या हमला), धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

ब्रीफ न्यूज

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पैसों के बदले इलाज वाले रैकेट में बस एक डॉक्टर कैसे? जांच एजेंसी को खनक रही ये बात

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के बदले पैसे लेने वाले डॉक्टर मनीष रावत की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए। सीबीआई की जांच में पता चला कि डॉक्टर सीधे किसी मरीज से पैसों की बात नहीं करता था, वो बिचौलियों के जरिए अपनी करतूत को अंजाम दिया जाता था।

नई दिल्ली: मरीजों को जल्द इलाज के नाम पर ठगने के लिए सफदरजंग अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष रावत ने एक पूरी टीम बना रखी थी। बिचौलिए के जरिये मनीष इन करतूतों को अंजाम देता था। पैसे की लेन-देन दीपक खट्टर के जरिए अंजाम दी जाती थी। दीपक से जब हरी झंडी मिलती थी, तब डॉक्टर मनीष मरीज को सर्जरी की तारीख देता था। रिपोर्ट में पाया गया है कि मरीजों से 25-30 हजार से लेकर 1.15 लाख रुपये तक इलाज के नाम पर ठगे गए हैं। मरीजों से सीधे बात नहीं करता था डॉक्टर डॉ. मनीष सीधे मरीज या तीमारदार से बात नहीं करता था। इंस्ट्रूमेंट बेचने वाले कनिष्क सर्जिकल के दीपक खट्टर के पास मरीज को भेजता था और उनके यहां सर्जरी में लगने वाले सामान खरीदने को कहा जाता था। दीपक सामान की कीमत से कई गुणा अधिक दामों पर मरीज को सामान देता था। इस एवज में दीपक खट्टर डॉक्टर मनीष की डिमांड पूरी करता था, चाहे वह कैश हों या डॉक्टर के घूमने जाने पर ट्रैवल एजेंट को रकम चुकाना हो। जानकारी के अनुसार, डॉक्टर मनीष के नाम पर अवनेश पटेल मरीज के तीमारदार से मिलता था और उससे बात कर उसे तैयार करता था, लेकिन शर्त पैसे की होती थी। वह मरीज को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट और जल्दी सर्जरी की तारीख दिलाने का भरोसा देता था।

सेक्स वर्कर के हत्यारे को ढूंढने के लिए पुलिस ने खंगाले 5000 नंबर, ऐसे खुल गया जीबी रोड मर्डर का राज

दिल्ली के जीबी रोड इलाके में सेक्स वर्कर की हत्या के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले और 5000 मोबाइल कॉल्स को वेरिफाई किया।

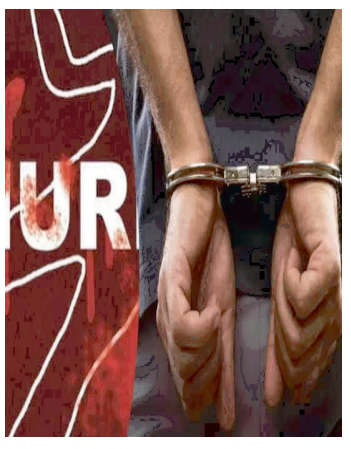

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जीबी रोड में 7 मार्च की दोपहर सेक्स वर्कर के मर्डर और कोठे के कर्मचारी को जख्मी करने के केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कमला मार्केट पुलिस ने राजस्थान के धौलपुर निवासी काका (19), हैपी (20) और पंजाब के संगरूर निवासी अनिल (22) को गिरफ्तार किया है। हैपी और अनिल संगरूर जेल में एक साथ बंद थे। दोनों पर पहले से 5-5 केस दर्ज हैं।

दुकान लूटने आए थे दिल्ली

डीसीपी (सेंट्रल) संजय कुमार सैन ने बताया कि जांच में पता चला कि काका मयूर विहार स्थित एक स्वीट शॉप में काम करता था। शॉप को लूटने के लिए ये बिहार से पिस्टल लेकर आए थे। फेस्टिवल सीजन में दुकान में काफी सेल होती है। इनका इरादा दुकान से लाखों रुपये लूटने का था। लेकिन ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद मौज-मस्ती के इरादे से जीबी रोड पहुंचे, जहां पैसों को लेकर विवाद में फायरिंग कर दी। इलाज के दौरान सेक्स वर्कर की मौत हो गई थी, जबकि कर्मचारी अब ठीक है।

पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी को खंगाला

कमला मार्केट थाने को 7 मार्च 2023 को कोठा नंबर 52 में गली चलने की कॉल मिली। 30 साल की सेक्स वर्कर और 28 साल के इमरान को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। शुरुआत में कातिलाना हमले का केस दर्ज किया गया। इलाज के दौरान सेक्स वर्कर की मौत हो गई। इसके बाद हत्या की धारा जोड़ी गई। पुलिस की टीमों ने आसपास के 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जिनमें तीन आरोपियों की साफ फोटो मिल गई। आरोपियों के एग्जिट रूट का पता किया तो वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाते दिखे। इससे अनुमान लगया कि आरोपी दिल्ली से बाहर के हैं। एक फुटेज में आरोपी फोन पर बात करते हुए दिखा। पुलिस ने इलाके से डंप डेटा यानी एक सेल टॉवर में एक्टिव मोबाइल नंबर उठाए।

5000 मोबाइल कॉल्स को किया वेरिफाई

पुलिस ने उस इलाके के करीब 5000 मोबाइल कॉल को वेरिफाई किया। इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली। पश्चिमी यूपी और पंजाब में छापेमारी कर काका, हैपी और अनिल को पकड़ लिया गया। हैपी और काका सगे भाई हैं। आरोपी कई आपराधिक मामलों में शामिल थे। डीसीपी ने कहा कि हैप्पी और अनिल की मुलाकात पंजाब की संगरूर जेल में हुई थी।

कंझावला कांड में पुलिस की 800 पेज की चार्जशीट, 7 आरोपी और 120 गवाह

कंझावला केस में दिल्ली पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 7 आरोपियों के खिलाफ 800 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। इस साल एक जनवरी को स्कूटी पर सवाल अंजलि नाम की एक लड़की को कारसवारों ने टक्कर मार दी थी। लड़की कार के पहियों में फंस गई थी और उसे कारसवारों ने सुल्तानपुरी से कंझावला तक घसीटा था।

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने कंझावला मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ शनिवार को 800 पेज की चार्जशीट दाखिल की। इस साल एक जनवरी की सुबह सुल्तानपुरी से कंझावला तक एक कार के नीचे फंसकर घिसटने से 20 वर्षीय युवती की मौत हो गई थी। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने चार्जशीट पर विचार करने के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है।

पुलिस ने दो जनवरी को इस मामले में दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। अदालत ने 2 अन्य आरोपियों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को पहले जमानत दे दी थी। एक सत्र अदालत ने दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

पुलिस के अनुसार, सात लोगों को गिरफ्तार किया गया और जांच पूरी होने के बाद करीब 117 गवाहों के साथ 800 पृष्ठों का एक आरोपपत्र तैयार किया गया। पुलिस ने कहा, 'जांच के दौरान इकट्ठा का गई सामग्री और सबूतों के आधार पर आरोपियों पर अभियोग चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री है।'

चार्जशीट के मुताबिक, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आशुतोष और अमित खन्ना पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसमें कहा गया है कि सभी आरोपियों पर आपराधिक षडयंत्र, सबूत नष्ट करने, अपराधी को पनाह देने, साझा मंशा और झूठी सूचना देने के आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने अमित खन्ना पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों की जान या निजी सुरक्षा खतरे में डालकर क्षति पहुंचाने के अतिरिक्त आरोप लगाए हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत पुलिस को 90 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल करना होता है। दिल्ली पुलिस ने हाल में मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) लगाई थी। उसने पहले गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था।

अंजलि सिंह (20) की नए साल के दिन तब मौत हो गई थी, जब उसकी स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और स्कूटी के कार में फंसने के बाद वह उसके साथ घिसटती चली गई थी।

कार सवार अधिवक्ता को बदमाशों ने बनाया निशाना, गोली मारकर उतारा मौत के घाट

नई दिल्ली। दिल्ली के द्वारका इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां एक कार सवार अधिवक्ता को गोली मार दी गई है। गोली लगने से अधिवक्ता की मौत हो गई है। मृतक अधिवक्ता का नाम वीरेंद्र कुमार नरवाल है। दिल्ली के द्वारका इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कार सवार अधिवक्ता को गोली मार दी गई है। गोली लगने से अधिवक्ता की मौत हो गई है। मृतक अधिवक्ता का नाम वीरेंद्र कुमार नरवाल है। जानकारी के मुताबिक, बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार थे और यह घटना द्वारका साउथ थाना क्षेत्र में घटी है।

मार्च का औसतन अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

लगातार चौथे दिन दिल्ली-NCR में हो रही बारिश, गर्मी में हो रहा सर्दी का अहसास

बीते दो सालों के मुकाबले में इस साल का मार्च कुछ ठंडा रहा। मार्च का औसतन अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

नई दिल्ली। मार्च के मध्य से मौसम लगातार बदलाव दिखने को मिल रहा है। धूप खिलने के बाद शाम होते-होते मौसम बदल जाता है। मौसम के इस बदले मिजाज के कारण चढ़ते पारे पर भी ब्रेक लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से चौथे दिन से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ओले गिरने की भी संभावना जताई है।

दिल्ली में एक मार्च से अब तक आठ दिन बारिश हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में शनिवार दोपहर बाद फिर से मौसम ने करवट ली और आसमान में काले बादल छा गए।

इससे पहले दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 28.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बृहस्पतिवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक 16.1 मिमी बारिश दर्ज की गई। जबकि 5:30 बजे तक 000.1 मिमी बारिश हुई।

बीते दो सालों के मुकाबले में ठंडा रहा मार्च

बीते दो सालों के मुकाबले में इस साल का मार्च कुछ ठंडा रहा। मार्च का औसतन अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे पहले 2022 में अधिकतम तापमान 32.9 और न्यूनतम तापमान 17.9 व 2021 में 33.1 और न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 2020 और 2019 में औसतन अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा था।

एक व तीन अप्रैल को हल्की बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार अभी दो दिन तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। एक व तीन अप्रैल को फिर से कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। तीन अप्रैल के बाद से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। एक बार फिर से तापमान 33 डिग्री तक पहुंच जाएगा।

गाजियाबाद में जल्द दौड़ेगी रैपिड ट्रेन: मुख्य सचिव ने किया सफर; बोले- वाह! कब पहुंच गए पता ही नहीं चला

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र रैपिड ट्रेन में दुहाई से साहिबाबाद स्टेशन पहुंते तो उन्होंने कहा वाह! कब पहुंच गए सफर का पता ही नहीं चला। यह सुनकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी NCRTC) के अधिकारियों के चेहरे पर चमक आ गई।

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र रैपिड ट्रेन में दुहाई से साहिबाबाद स्टेशन पहुंते तो उन्होंने कहा वाह! कब पहुंच गए सफर का पता ही नहीं चला। यह सुनकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी, NCRTC) के अधिकारियों के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने स्टेशन का भी निरीक्षण किया और कार्य की सराहना की।

रैपिड ट्रेन चलाने के लिए लेनी है अनुमति

रैपिड ट्रेन के साहिबाबाद स्टेशन पर पहुंचे एनसीआरटीसी के विनय कुमार सिंह ने कहा कि रैपिड ट्रेन चलाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। रैपिड ट्रेन चलाने से पहले कमिश्नर आफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी (सीएमआरएस) और मिनिस्ट्री आफ रेलवे से रैपिड ट्रेन संचालन की अनुमति लेना है। इसके लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अनुमति मिलते ही संचालन शुरू होगा।

रैपिड ट्रेन के साहिबाबाद स्टेशन की बदली काया

रैपिड ट्रेन के साहिबाबाद स्टेशन पर तेजी से काम चल रहा है। यहां पर चारदीवार बानकर अंदर पक्की सड़क का निर्माण कर दिया गया है। स्टेशन पर भी निर्माण का करीब 90 प्रतिशत काम हो गया है। लिंक रोड पर बना एफओबी रैपिड ट्रेन स्टेशन के अंदर है। लोग बिना किसी शुल्क के इस एफओबी का प्रोयग कर सकते हैं। रैपिड ट्रेन के स्टेशन के नीचे की सड़कें बनाई जानी शेष हैं। यहां तेजी से काम चल रहा है।

मुख्य सचिव को कई जगह मिला कूड़े का ढेर

रैपिड ट्रेन के साहिबाबाद स्टेशन व साहिबाबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद मुख्य सचिव का काफिला इंदिरापुरम के कैलास मानसरोवर की ओर चला। कई जगह कूड़े का ढेर और नाले में कचरा दिखा। इसपर उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी जताई। मुख्य सचिव ने कैलास मानसरोवर का निरीक्षण किया।

कैलास मानसरोवर भवन के हैंडओवर में देरी होने पर उन्होंने अधिकारियों से सवाल जवाब किया। मानसरोवर भवन के आस-पास बनी नालियों में प्लास्टिक और थर्माकोल की प्लेटें भी दिखी तो उन्होंने तुरंत साफ कराने का आदेश दिया।

इनसाइड

चोर को मिली अनोखी सजा, करनी होगी मरीजों की सेवा; भैंस चुराने के लिए मिली जेल

गाजियाबाद में एक जज ने भैंस चोरी के आरोपित को दोषी ठहराते हुए अनोखी सजा सुनाई है। अपना जुर्म स्वीकार करने वाले किशोर को सवा तीन महीने की जेल के साथ दो महीने मरीजों की सेवा करने की सजा सुनाई।

गाजियाबाद। गाजियाबाद में छोटे-मोटे अपराधों में जाने-अनजाने में शामिल होने पर जज भी कई बार सुधार का मौका देने में पीछे नहीं रहते। ऐसे ही एक मामले में एक किशोर ने जुर्म स्वीकार कर लिया तो जज ने भी सवा तीन महीने की जेल के साथ दो महीने मरीजों की सेवा करने की सजा सुनाई। इसी आदेश के क्रम में संबंधित दोषी किशोर (बाल अपचारी) मरीजों की सेवा करने जिला एमएमजी अस्पताल में पहुंच गया है। सीएमएस डा.मनोज कुमार चतुर्वेदी ने इसकी पुष्टि की है। जज के आदेश पर भैंस चोरी में दोषी किशोर अब मरीजों की सेवा के लिए भेजा जाएगा। शुक्रवार को जेल की सजा पूरी होने पर इस दोषी को मरीजों की सेवा करने के लिए जिला एमएमजी अस्पताल में भेजा गया तो सबसे पहले उसने सर्जिकल वार्ड में साफ-सफाई की। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा तीन मार्च 2023 को उसे भैंस चोरी का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

शादी समारोह में बेचने के लिए बनाए गए पांच लाख के अवैध पटाखे पकड़े, तीन गिरफ्तार

टीला मोड़ थाना पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में पटाखे बेचते थे। इसके लिए उन्होंने माल तैयार किया था। स्कूटी से आसपास के क्षेत्र में इसकी आपूर्ति करते थे।

साहिबाबाद। टीला मोड़ थाना पुलिस ने असालतनगर में पटाखे बनाने और बेचने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर पांच लाख रुपये के पटाखे बरामद किए हैं। शादी समारोह में बेचने के लिए यह पटाखे बनाए गए थे।

सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद भास्कर वर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली की टीला मोड़ थाना क्षेत्र के असालतनगर में पटाखे बनाए जा रहे हैं।

सूचना पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो कुछ बने और पटाखे तैयार करने के लिए विस्फोटक समेत अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपितों ने कबूला अपना जुर्म

पकड़े गए आरोपित असालतनगर के सुशील, तरुण और दीपांशु हैं। इनके पास से स्कूटी भी बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में पटाखे बेचते थे। इसके लिए उन्होंने माल तैयार किया था। स्कूटी से आसपास के क्षेत्र में इसकी आपूर्ति करते थे।

अधिकारी से परेशान किसान ने काटी नस, हालत गंभीर

गाजियाबाद। मोदीनगर में एक किसान ने शनिवार को समाधान दिवस पर अधिकारियों को सामने आपने हाथ की नस काट ली। बताया जा रहा है कि किसान लंबे वक्त से आबादी की संपत्ति की पैमाइश कराने की मांग कर रहे थे लेकिन लेखपाल किसान की सुन नहीं रहा था। गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित डिडौली गांव में एक किसान ने अधिकारियों के रवैए से परेशान हो अपने हाथ की नस काट ली है। शनिवार को समाधान दिवस में अधिकारियों को सामने अपने हाथ की नस काट ली। किसान की पहचान सुशील कुमार के रूप में हुई है। नस काटने के बाद किसान को आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनको मेरठ रेफर कर दिया गया। फिलहाल किसान की हलात गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि किसान आबादी की संपत्ति की पैमाइश कराने की मांग कर रहे थे। आरोप है कि कई बार शिकायत देने के बाद भी लेखपाल उनकी सुनवाई नहीं कर रहा था।

दो करोड़ रुपये की ठगी, बैंक की नीलामी में प्लॉट दिलाने का दिया था झांसा; मामला दर्ज

इंदिरापुरम के नीतिखंड एक में बैंक से नीलामी में 350 वर्ममीटर का प्लॉट दिलाने का झांसा देकर युवक से दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर ली। शातिरों ने सरकारी वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बना ली।

गाजियाबाद। इंदिरापुरम के नीतिखंड एक में बैंक से नीलामी में 350 वर्ममीटर का प्लॉट दिलाने का झांसा देकर युवक से दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर ली। शातिरों ने सरकारी वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बना ली। वैशाली के पीड़ित ने कौशांबी थाने में आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कौशांबी थाना क्षेत्र के वैशाली सेक्टर-एक में ईशांत राणा रहते हैं। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को उनकी मुलाकात दिलशाद गार्डन के कृष्ण कुमार और सुमित पंडित से हुई थी। कृष्ण कुमार ने उनसे बताया कि बैंक से नीलामी के प्लॉट को सस्ते दाम पर दिलाता है। झांसे में लेकर आरोपित ने बैंक की नीलामी के लिए रखे भूखंड के कूटरचित दस्तावेज दिखाए।

प्लॉट को सस्ते में दिलाने का दिया झांसा

आरोपियों ने नीतिखंड में चार करोड़ रुपये का 350 वर्गमीटर प्लॉट सस्ते में दिलाने का झांसा दिया। 50-50 लाख रुपये के चार ड्राफ्ट ले लिए। सरकारी वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बनाई। उसकी के आधार पर डिमांड ड्राफ्ट ले लिए। उन्होंने बैंक में जाकर प्लॉट और ड्राफ्ट के बारे में जानकारी की तो धोखाधड़ी की जानकारी हुई।

सरकारी वेबसाइट में खुलवाया था अकाउंट

कृष्ण कुमार और सुमित पंडित नाम के दो आरोपियों ने दिल्ली के एक बैंक में सरकारी वेबसाइट के नाम से खाता खुलवाया था। उन्होंने दोनों के खिलाफ कौशांबी थानें में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। पांच लाख रुपये ठगेलिंक रोड़ थाना क्षेत्र में रामपुरी में भी मकान बनवाने के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्वामी पर रुपये हड़पने का आरोप लगाया। मानव मित्तल ने बताया कि अक्तूबर 2020 में उन्होंने रोबिनसन नाम के ठेकेदार से घर बनाने के लिए करार किया था। इसकी एवज में उन्होंने पांच बार में पांच लाख रुपये दिए। एक साल तक काम शुरू नहीं किया। ठेकेदार के आफिस गए वहां ताला लगा था।

महाराजपुर पुलिस चौकी के पास बैंककर्मी से लूटा आइफोन, पकड़े जाने के डर से फेंककर हुए फरार

गाजियाबाद में पुलिस चेकपोस्ट के पास बैंककर्मी से आइफोन लूट लिया। पकड़े जाने के डर से बदमाश आइफोन सड़क पर फेंककर फरार हो गए। पुलिस चेक पोस्ट के पास लूट की घटना हुई। इससे साफ है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है।

साहिबाबाद: लिंक रोड थाना क्षेत्र के पैसेफिक माल के बाहर बदमाश ने निजी बैंककर्मी से आइफोन लूट लिया। पीड़ित शोर मचाते हुए बदमाशों के पीछे भागे। पकड़े जाने के डर से बदमाश आइफोन सड़क पर फेंककर फरार हो गए। महाराजपुर पुलिस चौकी के पास लूट की घटना हुई। इससे साफ है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है।

इंदिरापुरम में परिवार के साथ रहते हैं सुनील

इंदिरापुरम में सुनील पांडेय परिवार के साथ रहते हैं। वह दिल्ली के एक निजी बैंक में नौकरी करते हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम को वह बैंक से लौटकर पैसेफिक माल के बाहर किसी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर किसी परिचित का काल आ गया। वह मोबाइल पर बात कर रहे थे।

आसपास के लोगों ने बदमाशों का किया पीछा

तभी बदमाश आया और उनसे आइफोन लूटकर कौशांबी बस अड्डे की ओर भागने लगा। पीड़ित शोर मचाते हुए बदमाश के पीछे पैदल दौड़ पड़े। आसपास के लोग और आटो चालकों ने भी बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया। पकड़े जाने के डर से बदमाश आइफोन सड़क पर फेंककर दिल्ली की ओर भाग गया।

बेखौफ बदमाश, चौकी के पास की वारदात

रात आठ बजे ड्यूटी से घर लौटने वाले और लंबी दूरी पर जाने वाले लोगों की बस अड्डे पर भीड़ रहती है। पैसेफिक माल के बाहर ही आटो चालकों का जमावड़ा भी रहता है। दिल्ली से प्रवेश के दौरान पुलिस के बैरियर लगे हैं।

यातायात पुलिसकर्मी भी खड़े रहते हैं। चंद कदम पर महाराजपुर पुलिस चौकी है। बावजूद इसके बेखौफ बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इससे साफ है कि बदमाशों में पुलिस का तनिक खौफ नहीं है। इस संबंध में थाने पर कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कंट्रोल रूम पर भी कोई काल नहीं थी। शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। - ***मनीष बिष्ट, थाना प्रभारी निरीक्षक, लिंक रोड थाना।***

खुद ही लुटवा दिया अपना टैंकर, विरोधियों को फंसाने की थी योजना; 50 हजार में हायर किए लुटेरे

विरोधियों को फंसाने के लिए एक व्यक्ति ने अपना ही टैंकर लूटने की साजिश रच डाली। थाना वेवसिटी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर मामले का पर्दाफाश कर शनिवार को टैंकर मालिक चालक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

गाजियाबाद। विरोधियों को फंसाने के लिए एक व्यक्ति ने अपना ही टैंकर लूटने की साजिश रच डाली। थाना वेवसिटी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर मामले का पर्दाफाश कर शनिवार को टैंकर मालिक चालक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

डीसीपी ग्रामीण रवि कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित मथुरा के दलौता का उत्तम सिंह, छाता का हरिओम सिंह और फराह का नरेंद्र है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी उत्तम सिंह का टैंकर था, जिसे नरेंद्र चला रहा था। नरेंद्र ने 22 मार्च को थाना वेव सिटी पर आकर शिकायत दी थी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) पर डासना के पास सफारी सवार बदमाशों ने उनका टैंकर लूट लिया और उन्हें डासना के पास फेंककर फरार हो गए।

मथुरा के दो युवकों पर लगाया लूट का आरोप

नरेंद्र ने मथुरा के ही सौरभ व थान सिंह पर लूट का आरोप लगाया। कहा कि दोनों ने रंजिशन ऐसा किया है और मोबाइल भी लूट ले गए, जिस कारण वह पुलिस को फोन पर सूचना नहीं दे पाए। डीसीपी के मुताबिक घटना के बाद टैंकर दुहाई के पास से बरामद हो गया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उक्त दोनों व्यक्ति नहीं दिखे। घटनास्थल के पास नरेंद्र खुद ही सफारी कार में बैठता दिखा। नरेंद्र से पूछताछ की तो उसने हकीकत बता दी। इसके बाद पुलिस ने उत्तम और टैंकर को डासना से दुहाई ले जाकर छोड़ने वाले हरिओम को गिरफ्तार कर लिया। उत्तम ने बताया कि सौरभ व थान पूर्व में उसके मुनीम थे। दोनों से पैसों को लेकर विवाद हुआ, जिसमें उसने इन दोनों के खिलाफ मथुरा में केस दर्ज कराया था और बाद में दोनों ने उत्तम के खिलाफ रंगदारी मांगने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

50 हजार में लुटवाया अपना टैंकर

दोनों को लूट के मामले में फंसाने के लिए ही अपने कैंटर की लूट की साजिश रची थी। इसके लिए उसने चार लोगों को 50 हजार रुपये दिए। चारों ने सफारी कार से कैंटर का पीछा करते हुए डासना में ओवरटेक किया और योजना के तहत हरिओम टैंकर लेकर चला गया और नरेंद्र सफारी कार में बैठ गया। डासना में वह उतर गया और थाना वेव सिटी पहुंचकर शिकायत दी थी।

अब तक लॉन्च हुई ये दमदार कारें जो कई शानदार फीचर्स से लैस

इस साल ब्रेजा को सीएनजी ऑप्शन भी मिलेगा। अब तक भारतीय बाजार में कई दमदार कारें लॉन्च हो गई है। जो लोगो के बजट में भी है। इस लिस्ट में शामिल – Grand i10 Nios Maruti Brezza CNG Tata Updated Harrier Safari भी है।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक दमदार कारें लॉन्च हुई है। ये साल कार के मामले में अब तक काफी दमदार रहा है , कई बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों ने इस साल अपनी कई कारों को लॉन्च किया। जिसमें लग्जरी हैचबैक से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक शामिल है।

Maruti Grand Vitara CNG

भारतीय बाजार में इस साल जनवरी में सीएनजी किट के ऑप्शन के साथ आने वाली ये पहली एसयूवी बन गई। मारुति मिड - स्पेक डेल्टा और जेटा वेरिएंट पर सीएनजी किट दे रही है। इसकी कीमत 12.85 लाख रुपये से शुरू होती है। ग्रैंड विटारा सीएनजी 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ आती है, लेकिन 88PS और 121.5Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। इसे 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

Maruti Brezza CNG

भारतीय बाजार में इस कार की कीमत 9.14 लाख रुपये से शुरू होती है। इस साल ब्रेजा को सीएनजी ऑप्शन भी मिलेगा। इसे कंपनी ने मार्च में लॉन्च किया था। यह तीन वेरिएंट - LXi, VXi और ZXi में आती है। Brezza CNG में वही 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है।

Tata Updated Harrier/ Safari

टाटा हैरियर और सफारी के रेड एडिशन को लॉन्च किया गया है, इसे 2023 ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था। कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा, दोनों को कई दमदार फीचर्स मिलते हैं। जिनमें एक बड़ी टचस्क्रीन, ADAS फीचर मिलता है। जबकि दोनों एसयूवी का पावरट्रेन अब बीएस6 2.0 के अनुरूप भी है।

Hyundai Updated Alcazar

भारतीय बाजार में इस कार की कीमत 16.75 लाख रुपये से शुरू होती है। Hyundai ने इसमें नए 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया है। इससे पहले की पेशकश की गई 159 PS 2-लीटर पेट्रोल यूनिट को बदल दिया गया। जबकि सिक्स-स्पीड एमटी को बरकरार रखा गया है, नई टर्बो यूनिट पुराने सिक्स-स्पीड ऑटोमैटिक के बजाय सात-स्पीड डीसीटी का इस्तेमाल किया गया है।

Grand i10 Nios And Aura

भारतीय बाजार में इस कार की कीमत कीमत 5.69 लाख रुपये और 6.30 लाख रुपये से शुरू होती है। जनवरी 2023 में Hyundai ने फेसलिफ्टेड Grand i10 Nios और Aura को भारत में लॉन्च किया। इसमें 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है।

इनसाइड

पिछले महीने Ather ने बेचे 1,754 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स

पहले वाले मॉडल में 4 मोड मिलते थे वहीं न्यू जेनरेशन एथर 450 में अब कुल पांच राइडिंग मोड मिलते हैं जिसमें वॉर्प स्पोर्ट राइड इको और स्मार्ट इको राइडिंग मोड शामिल हैं। इको मोड पर इसकी टॉप स्पीड 50–55 के बीच आ रही है।

नई दिल्ली। Ather इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडियन इलेक्ट्रिक मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मार्च महीने में एथर एनर्जी कुल 11,754 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बेचने में कामयाब रही। इसके अलावा, फाइनेंसियल ईयर 2022-23 में कंपनी ने कुल 82,146 यूनिट्स ईवी की बिक्री की। एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर ने साल के शुरुआत में चार नए कलर को जोड़ा गया है, जिसमें Lunar Grey, Cosmic Black, True Red, Salt Green शामिल है। एथर का कहना है कि 450X गूगल मैप्स के साथ दुनिया का पहला स्कूटर है। एथर अब वेक्टर मैप पेश कर रहा है जो ज़ूमिंग, रोटेटिंग, परिप्रेक्ष्य परिवर्तन और यहां तक कि लेयरिंग को भी सक्षम बनाता है। Ather इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो गूगल मैप है उसको और भी ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है। ग्राहक अब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाते समय लाइव ट्रैफिक नेविगेशन का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा, टक स्क्रीन को फ़ोन के तर्ज पर चेंज किया गया है। Ather इलेक्ट्रिक स्कूटर की सीट को और भी बेहतरीन बना दिया गया है।

पुरानी वाली एथर से काफी एडवांस हैं नई वाली स्कूटर

पहले वाले मॉडल में 4 मोड मिलते थे, वहीं न्यू जेनरेशन एथर 450 में अब कुल पांच राइडिंग मोड मिलते हैं, जिसमें वॉर्प, स्पोर्ट, राइड, इको और स्मार्ट इको राइडिंग मोड शामिल हैं। इको मोड पर इसकी टॉप स्पीड 50-55 के बीच आ रही है। वहीं इसके Warp मोड में मैक्सिमम पॉवर आउटपुट मौजूदा 6 kW (8.1 hp) से बढ़कर 6.4 kW (8.7 hp) हो गया है। इससे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड पुराने मॉडल की तुलना में थोड़ा अधिक हो गई है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में पहले बैटरी पर 3 साल की वारंटी मिलती थी। कंपनी ने इसे बढ़ा कर 5 साल/60,000 किलोमीटर कर दिया गया है। यह ऑफर पुराने ग्राहकों को भी फ्री में मिलेगा।

TVS बाइक से लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटर तक, पिछले महीने खूब बिकीं टीवीएस की टू-व्हीलर्स

TVS Sales Report March 2023 कंपनी ने कहा कि उन्होंने टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री मार्च 2023 में 15364 यूनिट्स की। जो कि एक साल पहले सामान अवधि में 1799 इकाई की बिक्री हुई थी।

नई दिल्ली। TVS ने पिछले महीने 3,17,152 मोटरसाइकिलों को बेचने में कामयाब रही। जो मार्च 2022 में बेची गई 3,07,954 बाइक्स की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक हैं। टीवीएस मोटर कंपनी ने एक बयान में कहा कि कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री पिछले महीने 5 प्रतिशत बढ़कर 3,07,559 इकाई हो गई, जबकि मार्च 2022 में यह 2,92,918 इकाई थी।

घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री

TVS घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री पिछले महीने 2,40,780 इकाई रही, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 1,96,596 इकाई थी, जो 22 प्रतिशत अधिक है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की भी रही डिमांड

कंपनी ने कहा कि उन्होंने टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री मार्च 2023 में 15,364 यूनिट्स की। जो कि एक साल पहले सामान अवधि में 1,799 इकाई की बिक्री हुई थी।

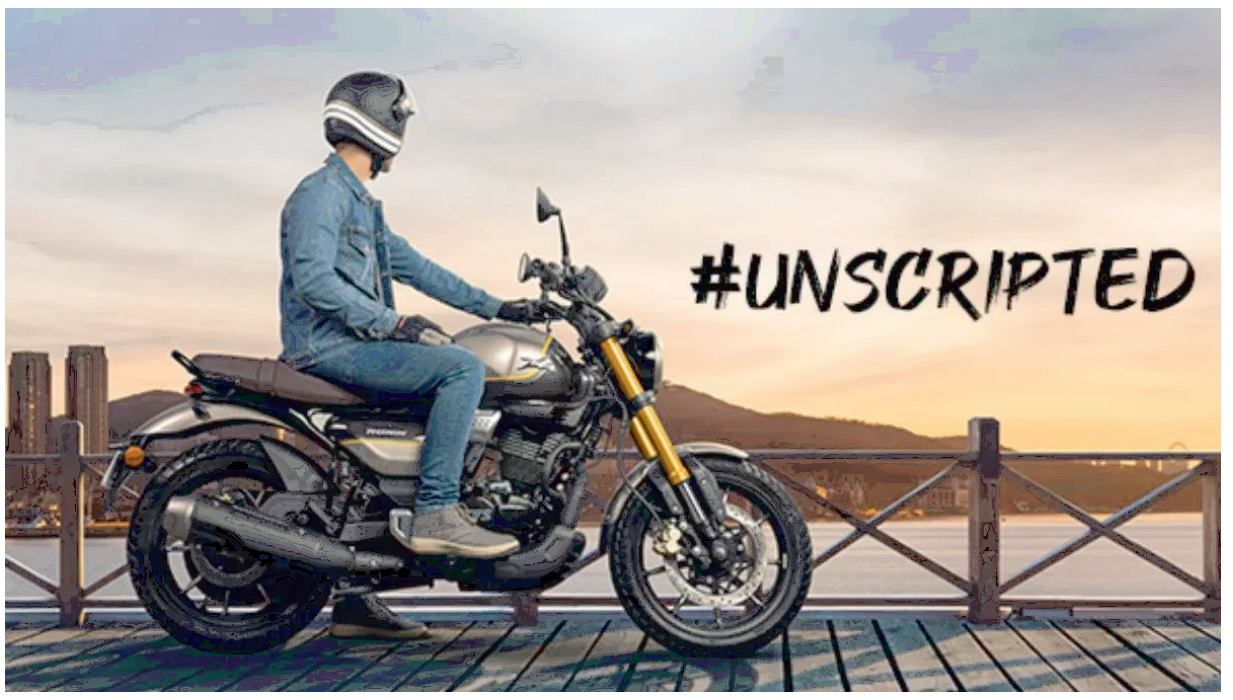

थ्री व्हीलर्स की बिक्री भी गिरावट दर्ज

मार्च 2022 में 15,036 इकाइयों की तुलना में पिछले महीने तिपहिया वाहनों की बिक्री 9,593 इकाई रही। मार्च 2023 में कुल निर्यात भी कम होकर 75,037 यूनिट रहा, जबकि मार्च 2022 में यह 1,09,724 यूनिट था।पिछले महीने दोपहिया वाहनों का निर्यात 66,779 इकाई रहा, जो एक साल पहले 95,962 इकाई था।

TVS Apache RTR 160 2v राइडिंग एक्सपीरिएंस

अगर आप डेली सिटी में ट्रैवल करते हैं और आपको कई बार ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है तो आपके लिए बाइक बेस्ट है। वहीं लॉन्ग ट्रिप के लिए ये बाइक चुनते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। बाइक की कंट्रोलिंग मुझे काफी अच्छे लगी, पिकअप भी ठीक था, लेकिन अर्बन मोड से जब आप स्पोर्ट्स मोड में चेंज करते हैं तो तुरंत वो स्पोर्ट्स मोड वाली फील नहीं आती है। हालांकि, कुछ सेकेंड दूर चलने के बाद आपको स्पोर्ट मोड वाली फिलिंग मिल जाएगी।

80-85 की स्पीड जब मैं क्रॉस किया तो बाइक थोडा सी लहराई (वाइब्रेट की)। हालांकि, इससे राइडिंग पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है तो मेरे हिसाब से मुझे इसको हैंडल करने, बैठने, ट्रैफिक के दौरान चालाने में कोई परेशानी नहीं हुई। पहले वाली बाइक की तुलना में इस बाइक के वजन को 2 किलो हल्का कर दिया गया है। आप इसपर बैठ कर अपने हिसाब से आगे पीछे बाइक को बैठे-बैठे कर सकते हैं।

Royal Enfield ने मार्च के महीने में किया 72,235 यूनिट्स की सेल, कंपनी करेगी 350 सीसी मोटरसाइकिल में विस्तार

Royal Enfield की मार्च की सेल्स रिपोर्ट आ गई है। वाहन निर्माता कंपनी की सेल कुल सात प्रतिशत बढ़ गई है। जबकि एक साल पहले के महीने में यह 58477 इकाई थी जिसमें 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड लोगों के दिलो पर खासतौर से युवाओं को अधिक पसंद आती है। वाहन निर्माता कंपनी ने मार्च के महीने में 72,235 यूनिट्स की सेल की है। कंपनी की सेल कुल सात प्रतिशत बढ़ गई है। इसकी तुलना पिछले साल के इसी महीने से करें तो कंपनी ने 67,677 यूनिट्स की सेल की थी। कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि समीक्षाधीन महीने में घरेलू बिक्री 59,884 इकाई रही, जबकि एक साल पहले के महीने में यह 58,477 इकाई थी, जिसमें 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, रॉयल एनफील्ड ने कहा कि उसने 8,34,895 मोटरसाइकिलों की रिकॉर्ड कुल बिक्री के साथ 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त वर्ष 22 में कंपनी की बिक्री 6,02,268 यूनिट रही। वित्त वर्ष 2022 में 81,032 यूनिट की तुलना में निर्यात भी वित्त वर्ष 2023 में 1,00,055 यूनिट के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था, जो 23 प्रतिशत अधिक था।

350 सीसी वाली मोटरसाइकिल पर कंपनी कर रही है काम

आपको बता दें, रॉयल एनफील्ड अपनी 350 सीसी लाइनअप पर काफी तेजी से काम कर रही है। कंपनी की 350 सीसी वाली मोटरसाइकिल सबसे अधिक बिकती है। यही वजह है कि भारी डिमांड को देखते हुए कंपनी अपने इस सेगमेंट के पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। रॉयल एनफील्ड की नई 350 सीसी बाइक का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। कंपनी जल्द ही इन 350सीसी बाइक्स को लॉन्च कर सकती है।

ROYAL ENFIELD SHOTGUN 350 BOBBER

भारतीय बाजार में कंपनी की आने वाली बाइक की लिस्ट में ROYAL ENFIELD SHOTGUN 350 BOBBER बाइक का नाम भी शामिल है। इसको लेकर ये उम्मीद किया जा रहा है कि कंपनी इसे जल्द लॉन्च कर सकती है। नई रॉयल एनफील्ड शॉटगन 350 में 346cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है।

Tata Motors की हुडंई से कम बिकीं कारें, इन सेगमेंट में हुई अच्छी ग्रोथ

टाटा मोटर्स पीवी की बिक्री मार्च 2023 में 44044 इकाइयों की बिक्री के साथ टाटा मोटर्स की कारों की बिक्री काफी हद तक नेक्सॉन और पंच की अधिक डिमांड के कारण उभरी हैं। ये दोनों वाहन ब्रांड के लिए लगातार अच्छा वॉल्यूम बना रहे हैं।

नई दिल्ली। Tata Motors Hyundai से दूसरा स्थान छीन लिया था, लेकिन अधिक समय तक इस पर अपना कब्जा नहीं जमा पाई है। मार्च 2023 के महीने में, Tata Motors की बिक्री 44,044 यूनिट्स रही, जबकि Hyundai 50,600 यूनिट्स पर लगभग 6K यूनिट्स की बढ़त बनाने में कामयाब रही। हालांक, Tata ने नई कार लॉन्च करने की योजना बनाई गई है, जो आने वाले महीनों में अधिक बिक्री की उम्मीद करती है।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स

टाटा मोटर्स पीवी की बिक्री मार्च 2023 में 44,044 इकाइयों की बिक्री के साथ, टाटा मोटर्स की कारों की बिक्री काफी हद तक नेक्सॉन और पंच की अधिक डिमांड के कारण उभरी हैं। ये दोनों वाहन ब्रांड के लिए लगातार अच्छा वॉल्यूम बना रहे हैं। मार्च 2022 में टाटा द्वारा बेची गई 42,293 इकाइयों की तुलना में, 4.14% YoY वृद्धि दर्ज की गई थी। फरवरी 2023 में बेची गई 42,865 इकाइयों के विपरीत, टाटा मोटर्स ने 2.75% MoM वृद्धि देखी।

टाटा मोटर्स घरेलू बिक्री

मार्च 2023 में Tata Motors ने कुल 89 हजार से अधिक गाड़ियों की बिक्री की है। यह 3 फीसद YoY ग्रोथ है। CV की घरेलू बिक्री 45 हजार यूनिट रही, जो 2 फीसद YoY बढ़ रही है। सीवी निर्यात 1,516 इकाइयों पर रही, जहां 42 फीसद की गिरावट दर्ज की गई।

कंपनी ने कुछ समय पहले ही 50 लाख गाड़ियों के प्रोडक्शन का आंकड़ा पार किया था। ऑटो प्रमुख ने 2004 में 10 लाख उत्पादनका आंकड़ा हासिल किया था। वहीं, 2010 में 20 लाख मील का पत्थर हासिल किया गया था। साल 2015 में टाटा ने 30 लाख यूनिट और 2020 में 40 लाख यूनिट को पार कर लिया। वहीं, अब कंपनी को 50 लाख उत्पादन का आंकड़ा हासिल करने

आगामी चुनाव और विपक्ष की रणनीति

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

यही कारण है कि अमरीका सरकार सार्वजनिक रूप से कह रही है कि हम हिंदुस्तान की सरकार की गतिविधियों पर तीखी नजर रखे हुए हैं। बीबीसी मोदी विरोधी ताकतों को कच्चा माल मुहैया करवा रही है'

लोकसभा का आगामी चुनाव अत्यन्त महत्वपूर्ण होता जा रहा है। देश में भी और विदेश में भी। उसका कारण है। आज तक देश में तीन प्रकार की सरकारें रही हैं। कांग्रेस द्वारा अपनी कार्यकारिणी में भारत के विभाजन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त, ब्रिटिश सरकार ने भारत को डोमीनियन का दर्जा देना स्वीकार कर लिया था और उस डोमिनियन की कमान पंडित जवाहर लाल नेहरू को सौंप दी थी। लेकिन यह ध्यान रखा कि डोमीनियन का गवर्नर जनरल अभी भी ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि लार्ड माऊंटबेटन ही रहे। इसका ब्रिटिश सरकार को लाभ यह हुआ कि माऊंटबेटन ने जम्मू कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में करवा दिया, मामला सुरक्षा परिषद में लटका दिया जिसके कारण देश के संविधान में अनुच्छेद 370 ने जन्म ले लिया। यह कांग्रेस की पहली सरकार थी, जिसने देश के लिए भावी रणनीति तय कर दी थी। कांग्रेस की यह सरकार मोटे तौर पर 1947 से लेकर 1997 तक चली। बीच में तीन-चार साल गैर कांग्रेसी सरकारें रहीं, लेकिन वे सरकारें तकनीकी तौर पर ही गैर कांग्रेसी कही जा सकती हैं क्योंकि वे सरकारें भी मोटे तौर पर व्यक्तिगत कारणों से कांग्रेस से रूठे हुए कांग्रेसियों की ही सरकारें थीं। इसलिए देश के शासन में किन्हीं नीतिगत परिवर्तनों की आशा नहीं की जा सकती थी। सरकार की देश को लेकर सोच और दिशा वही रही जो पंडित जवाहर लाल नेहरू और लार्ड माऊंटबेटन तय कर गए थे।

यही कारण था कि पाकिस्तान बार-बार भारत पर हमले करता रहा, भारतीय सेना शौर्य का प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सरकारें मेज पर सेना की जीत को हार में बदलती रहीं। चीन ने भारत के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और भारत सरकार फिर भी उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर दिलवाने के लिए दिन-रात एक करती रही। 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा सरकार रही। परन्तु वह चौबीस परस्पर विरोधी दलों की सरकार थी। अगले दस साल तक पुनः कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाले रखी। लेकिन यह भी तकनीकी तौर पर ही कांग्रेस की सरकार कही जा सकती थी। वास्तव में यह सोनिया माईनो गान्धी, जिसने खाँटी कांग्रेसी सीता राम केसरी को बैठक में से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था, की सरकार ही थी जो वह अपने दरबारियों जिन्हें नैशनल कौंसिल का नाम दे रखा था, के माध्यम से चला रही थीं। लेकिन भारतीय संविधान में सरकार के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता है, इसलिए उस पद पर मनमोहन सिंह जी को बिठा रखा था। इसलिए यदि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के छह साल निकाल दिए जाएं तो 1947 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के लोगों की सरकार ही रही। ये सरकारें चीन, अमेरिका और पाकिस्तान को बहुत ही मुफीदकारी लगती थीं। सोनिया माईनो गान्धी की सरकार तो वैटिकन के राष्ट्रपति को एक प्रकार से अपनी ही सरकार लगती थी। यही कारण था कि उन दिनों चर्च हर रोज़ दिवाली मनाता था। इन सरकारें ने मानसिक रूप से ही तय कर रखा था कि देश को विश्व राजनीति के पिछवाड़े में ही रखना है। आर्थिक नीतियां इस प्रकार की रखी जाएं कि औद्योगीकरण में देश रेंगता रहे। जहां तक देश की सांस्कृतिक पहचान का प्रश्न था, इन सरकारों का निश्चित मत था कि देश की संस्कृति ही देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। यह देश का मानसिक पिछड़ापन है। इसलिए ये सरकारें भारत के विसंस्कृतिकरण को नीति का हिस्सा बनाती थीं। कुल मिला कर देश को विश्व शक्तियों का पिछलग्गू बना कर रखना भारत सरकार की आधिकारिक नीति थी। यही कारण था कि यह नीति रूस, चीन और अमेरिका को एक साथ ही अपने अनुकूल लगती थी। लेकिन 2014 में देश के लोगों ने इन नए-पुराने कांग्रेसियों से सत्ता लेकर नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंप दी। पिछले तीस साल से बीस-बीस दल मिल कर भारत जैसे महान देश की सरकार चला रहे थे। ऐसी सरकारें देश को कोई निश्चित दिशा नहीं दे पाई। दिशाविहीन भारत उन सभी महाशक्तियों को अनुकूल लगता है जो दुनिया की दिशा अपने राजनीतिक व आर्थिक हितों के अनुकूल ढालना चाहती हैं।

लेकिन नरेन्द्र मोदी के आने से सारा परिदृश्य ही बदल गया। सबसे पहले तो देश ने सीमाओं को लेकर ढुलमुल नीति से किनारा किया। पूर्वोत्तर भारत में विकास ने गति पकड़ी। सडक़ें, रेल की पटरी बनने लगीं। हवाई अड्डे बनने लगे। सबसे बढ़ कर तिब्बत की सीमा से लगते इलाके में विकास होने लगा। जाहिर है इससे चीन तिलमिलाता। चीन तभी तक भारत का मित्र है जब तक भारत चीन की गतिविधियों की ओर से आंख मूंदे रहता है। जब भारत जागता है तो चीन को लगता है भारत अपनी परम्परा को छोड़ रहा है। चीन के लिहाज़ से भारत की परम्परा भारत द्वारा तिब्बत और लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाक़ों पर चीन को कब्जा कर लेने की अनुमति देना ही है। लेकिन अब भारत डोकलाम और गलवान में चीन से भिड़ रहा है। जाहिर है चीन चाहेगा कि किसी भी तरह मोदी की सरकार हटनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सरकार के वे पुराने दिन लौट आएं। इसी प्रकार पाकिस्तान की स्थिति है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अपने आतंकवादी भेजता था। हुर्रियत कान्फ्रेंस के नेताओं को दिल्ली में अपने दूतावास में बुला कर ख़ातिरदारी करता था। मुम्बई में नरसंहार करता करवाता था। भारत में एटीएम (अरब, तुर्क, मुगल) मूल के लोग खुले आम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की हिस्सेदारी की बात करते थे। लेकिन सोनिया गान्धी की सरकार कहा करती थी कि बेचारा पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का शिकार है। लेकिन नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आ जाने से कांग्रेसी सरकारों और पाकिस्तान का वह सुहाना सफर ख़त्म हो गया। पाकिस्तान ने पुलवामा में हमला करवाया तो भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुस कर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ।

कांग्रेसियों और पाकिस्तान दोनों के चेहरे सूख गए। दोनों ने एक स्वर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। लेकिन मोदी सरकार यहीं नहीं रुकी। अनुच्छेद 370 के बहाने कश्मीर में पाकिस्तान की हिस्सेदारी बताने वाले गैंग का मुंह अनुच्छेद 370 को मार कर बंद कर दिया। कांग्रेस और पाकिस्तान ने इतना चिल्लाना शुरू किया कि भारतीयों को यह अनुमान लगाना मुश्किल हो गया कि अनुच्छेद 370 के हटने पर कौन ज्यादा दुखी है? कांग्रेस या पाकिस्तान? यही कारण है पाकिस्तान भी चाहता है कि किसी भी तरीके से हिन्दुस्तान से मोदी सरकार हटनी चाहिए। अमेरिका, इंग्लैंड को हिन्दुस्तान तब तक ही प्यारा लगता है जब तक वह पूरी वफादारी से ब्रिटिश काल की विरासत ढोता रहे और अपनी सनातन विरासत को छोड़ कर ब्रिटिश सत्ता की विरासत को ही अपनी विरासत घोषित कर दे। अभी तक कांग्रेस सरकारें यही करती आ रही थीं। लेकिन मोदी सरकार आ जाने के बाद मामला बदल गया। मोदी संयुक्त राष्ट्र से योग दिवस की घोषणा करवाते हैं। ब्रिटिश काल की शिक्षा नीति त्याग कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाते हैं। विदेशी मेहमानों को लेकर ताजमहल की जगह महाबलीपुरम लेकर जाते हैं। कोरिया के लोग अपना संबंध अयोध्या से जोड़ रहे हैं। भारत विश्व की आर्थिक शक्ति बनने के लिए दौड़ रहा है। कोरोना वैक्सीन में भारत विश्व के देशों की सहायता कर रहा है। ऐसा भारत भारतीयों को अच्छा लग रहा है, विदेशी ताक़तों और भारत में रह कर इन्हीं ताकतों के पिछलग्गू बने लोगों को नहीं। इसलिए वे सभी चाहते हैं कि किसी तरह 2024 में मोदी सरकार को हटाया जाए। यही कारण है अमेरिका सरकार सार्वजनिक रूप से कह रही है कि हम हिन्दुस्तान की सरकार की गतिविधियों पर तीखी नजर रखे हुए हैं। बीबीसी अपने तरीके से मोदी विरोधी ताकतों को कच्चा माल मुहैया करवा रही है।

संपादक की कलम से

निर्माण के पाप-पुण्य

नवनिर्माण की हिस्सेदारी में गुणवत्ता के हिस्से अगर बिखर जाएं, तो यह सदी के गुनाह क्यों न माने जाएं। हमीरपुर में एक निर्माणाधीन पुल के गिरने ने बता दिया कि हमारी उपलब्धियों में कहां-कहां सुराख हैं। यह एक स्लैब का गिरना नहीं, बल्कि निर्माण के डिजाइन, विभागीय कार्यशैली और विकास के कार्यों के कार्यान्वयन पर उठ रहे सवाल हैं। हम इसे एक छोटी से गुस्ताखी, लापरवाही या अनुभवहीनता मान कर टाल सकते हैं, लेकिन यह उस परिपाटी का एक हिस्सा है जिसके तहत पूरे हिमाचल में सरकारी परियोजनाओं की मिट्टी पलीद हो रही है। जाहिर है बजट या धन की कमी नहीं है और न ही परियोजनाओं की कमी, लेकिन ढर्रा कुछ ऐसा बन गया कि इंजीनियरिंग में न तो नवाचार और न ही गुणवत्ता के प्रति संवेदनशीलता सामने आ रही है। हर किसी को सिर्फ एक उद्घाटन पट्टिका चाहिए और जिसके जरिए यह साबित करना होता है कि काम हो गया। यूं तो हिमाचल में निर्माण कार्यों में सभी विभागों ने अपने तकनीकी विंग खोल रखे हैं, लेकिन पीडब्ल्यू विभाग की मुख्य भूमिका सामने नहीं आ रही है। पर्वतीय परिवेश के लिए विकास के मायने, विकास साधन-संसाधन, विकास के समाधान और इसकी विशिष्टता केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसकी खास परिकल्पना में अनुसंधान व तमाम चेतावनियों के प्रति संज्ञान की जरूरत है। सर्वप्रथम स्थल चयन की प्रक्रिया में भूमि की प्रवृत्ति, भौगोलिक परिस्थिति और डिजाइन की भूमिका को निर्धारित करने का संकल्प सामने आना चाहिए। पुल, पुलिया और भविष्य के सेतु बनाने में बेशक सामग्री तो एक जैसी ही रहेगी, लेकिन अंतर सिर्फ प्रतिज्ञा और कमठता का है। पूरे हिमाचल में देखें तो इमारतें या अन्य निर्माण तो धड़ाधड़ हो रहा है, लेकिन भविष्य का निर्माण देखना बाकी है। अस्पताल, अदालत, पुस्तकालय, स्कूल, कालेज या धार्मिक स्थलों के विकास में एक जैसी वास्तुकला, डिजाइन या परिकल्पना नहीं हो सकती। आज भी हम शिमला में ब्रिटिश शासन के दौरान निर्मित भवनों के समानांतर कोई नई इमारत नहीं सजा पाए। इसका उदाहरण न्यू शिमला की अफरातफरी में परिलक्षित है। हमारा बजट अग्रगामी हो सकता है, लेकिन विकास के पैरामीटर तय नहीं हो रहे। इसलिए पुल के एक स्लैब का गिरना केवल सामग्री का गिरना नहीं हो सकता, बल्कि स्थल चयन, डिजाइन व विकास की दौड़ में लक्ष्यों का गिरना भी है। ये खतरे केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि निजी तौर पर भी पहाड़ों से मानव का संघर्ष अब कोताही पर उतर आया है। उदाहरण के लिए अतीत का सोलन शहर आज के शहरी आधिपत्य में अपने अस्तित्व को नजरअंदाज कर रहा है। सोलन के वर्तमान में न शहरी विकास विभाग की कोई परिकल्पना दिखाई देती है और न ही बढ़ती चुनौतियों का किसी ने संज्ञान लिया। देखते ही देखते यह प्रदेश का अपार्टमेंट शहर बन गया, लेकिन इसकी कोई परिभाषा सामने नहीं की गई। इसी तरह पूरे प्रदेश में पहाड़ कट रहे हैं, प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते अवरुद्ध हैं और बिना मानदंड के घाटी की ओर से सडक़ों के किनारे पर इमारतों के झुंड आसीन हैं। राजनीतिक दखल से टीसीपी की नजर में आए ग्रीन क्षेत्रों में भी निर्माण की अनुमति अगर रूटीन बन गई है, तो हर शहर में कहीं न कहीं कब्रिस्तान खड़ा है। सरकारी निर्माण को पाप-पुण्य में न बांटे, तो भी प्रगति के मानकों में हिमाचल अपने भविष्य की अधोसंरचना के प्रति, इस तरह की लापरवाही तो बरत ही रहा है कि निर्माण की गुणवत्ता पर प्रश्न चस्पां हैं।

चर्चा

जर्मन लोकतंत्र न पढ़ाए

राहुल गांधी और भारतीय लोकतंत्र के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर टकराव की मुद्रा में हैं। जर्मनी के विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में अपेक्षा की गई है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करते हुए न्यायिक स्वतंत्रता के मानकों और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मनी का आभार जताया कि उसने भारत में लोकतंत्र के साथ किए जा रहे समझौतों पर ध्यान दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान कुछ और बयां करता है। दरअसल अब इस अध्याय को बंद किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी तकनीकी और संवैधानिक तौर से खारिज की गई है। इस संदर्भ में गौरतलब है कि जब सर्वोच्च अदालत ने दो साल की घोषित न्यायिक सजा पर संसद और विधानसभा सदस्यता रद्द करने का फैसला सुनाया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया था। वह न्यायपालिका का पलटजवाब था।

अध्यादेश के जरिए दागी और सजायाफ्ता नेताओं को बचाने के प्रावधान किए गए थे। राहुल गांधी अचानक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया गए और उस अध्यादेश की प्रतिलिपि फाड़ते हुए बोले- 'नॉनसेंस!' नतीजा यह हुआ कि कैबिनेट को वह अध्यादेश वापस लेने का निर्णय लेना पड़ा। आज अध्यादेश कानूनी तौर पर लागू होता, तो राहुल की सांसदी बच जाती। बहरहाल अब सर्वोच्च अदालत का फैसला लागू है। उसके तहत 15-20 नेताओं की सांसदी रद्द की जा चुकी है। कुछ उदाहरण हैं-चारा घोटाले में जगदीश शर्मा, जद-यू सांसद मित्रसेन यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस सांसद रशीद मसूद, पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और पूर्व कांग्रेस सांसद राशिद अल्वी आदि। किसी की खारिज सांसदी पर, किसी भी देश ने, हमें लोकतंत्र और न्यायिक स्वतंत्रता का पाठ नहीं पढ़ाया। जर्मनी पर तानाशाह हिटलर ने भी शासन किया था, लिहाजा उसकी परंपराओं में तानाशाही है। वह दुनिया के सबसे बड़े और प्राचीनतम लोकतंत्र भारत को क्या नसीहत दे सकता है? राहुल गांधी ने लंदन में यह इच्छा जरूर जाहिर की थी कि अमरीका और यूरोप के देश खुद को लोकतंत्र का रक्षक मानते हैं। वे ध्यान दें कि एक बड़े देश के लोकतंत्र में क्या हो रहा है? विदेशी दखल की उनकी इच्छा आंशिक तौर पर पूरी हो गई है। राहुल के सामने कानूनी विकल्प आज भी हैं। उन्हें भारत के कानून और विदेशी दखल में से एक विकल्प चुनना है। वह अदालत में चुनौती अब भी दे सकते हैं। उन्हें अदालत में जाना भी चाहिए, क्योंकि पटना उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल को पेश होने का नोटिस भी भेजा है। 'मोदी उपनाम वाले ही चोर..' वाले संदर्भ में भाजपा सांसद एवं बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी मानहानि का केस किया था। राहुल अदालत में गुहार लगा कर ऐसे सभी मामलों की एक ही जगह सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। अदालत के जरिए ही जिस तरह लक्षद्वीप के सांसद मुहम्मद फैज़ल की सांसदी बहाल की गई है, उसी तरह राहुल के संदर्भ में भी संभव है। जर्मनी का बयान कितना कारगर साबित हो सकता है? अमरीका और यूरोपीय देश मानवाधिकार, अल्पसंख्यक सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आज़ादी संबंधी नसीहतें भारत सरकार को देते रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र को कौन सबक सिखा सकता है? भारत के सभी बड़े देशों से अच्छे रिश्ते हैं। यह 1960, '70, '80 और '90 के दशकों वाला भारत नहीं है। भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। राहुल गांधी का मामला भारत का अपना अंदरूनी मामला है। एक और विनम्र सलाह राहुल गांधी के नाम है कि चाटुकार कांग्रेसियों पर जरा अंकुश लगाएं।

राहुल गांधी को मिली सजा के सबक

योगेन्द्र योगी

क्षेत्रीय दलों में ज्यादातार नेताओं के परिवार का बोलबाला है। इसीलिए सत्ता पाने की प्रतिस्पर्धा से राजनीति में गिरावट का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के पास अन्य दलों की तुलना में लोकसभा में सीटें बेशक कम हों, किंतु विपक्षी दलों में कांग्रेस एकमात्र पार्टी है, जिसकी तीन राज्यों में सत्ता होने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का नेटवर्क है। इससे कांग्रेस की जिम्मेदारी अन्य दलों से कहीं ज्यादा है। सार्वजनिक जीवन में संयमित आचरण और ईमानदारी के मानदंड स्थापित करने की ज्यादा जिम्मेदारी भी कांग्रेस पर है। सत्ता पक्ष की नीतियों की आलोचना करना स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा और जरूरत है। इसके विपरीत यदि व्यक्तिगत आक्षेप लगा कर राजनीति को गंदा किया जाए तो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हाशिए पर चले जाएंगे। इससे एक नए तरीके का विद्रूप राजनीति का माहौल देश में बनेगा। ऐसे वातावरण की कीमत देश को पिछडने से चुकानी पड़ेगी। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि राहुल को मिली सजा और सांसद का पद जाने से देश के नेताओं को सार्वजनिक तौर पर बोलने से पहले सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा'

देश के विकास की बागडोर नेताओं के हाथ में है। देश में लोकतांत्रिक शासन पद्धति होने से उम्मीद यही की जाती है कि नेता देश को नई दशा-दिशा देंगे। देश और समाज के समक्ष अपने आचरण और व्यवहार से आदर्श पेश करेंगे। इसके विपरीत यदि नेता ही अपनी जुबान पर लगाम नहीं रख पाएं तो देश के भले की उम्मीद नहीं की जा सकती। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि नेता बदजुबानी पर उतर आएं। ऐसे बेलगाम नेता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संयम और अनुशासन बरतने का क्या संदेश देंगे। आत्मनुशासन के बजाय नेताओं को कानून के जरिए संयत भाषा और आचरण से नियंत्रित किए जाने की कार्रवाई उनको आईना दिखाने वाली मानी जाएगी। अपशब्द कहने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा और उससे गई संसद की सदस्यता से उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के नेता अपनी जुबान पर लगाम लगाएंगे। नेताओं को जुबान पर लगाम का सबक सिखाने के मामले में राहुल गांधी को मिली सजा मील का पत्थर साबित होगी। इससे कम से कम सार्वजनिक रूप से गरिमा के प्रतिकूल टिप्पणी करने की कीमत चुकाने से नेताओं में डर पैदा होगा।

यह पहला मौका नहीं है जब किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को अदालत से मिली सजा और उसके बाद संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी हो। इससे पहले राजद के नेता लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता सहित कई नेताओं को विधानसभा और लोकसभा से सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। राहुल के सिवाय इन नेताओं को आपराधिक और दूसरे मामलों में जेल की सजा सुनाए जाने पर सदस्यता खोनी पड़ी। इसके विपरीत राहुल को एक जाति विशेष पर अपशब्द कहने के कारण सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। देश की विभिन्न अदालतों में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर नेताओं के खिलाफ दर्जनों मानहानि और आपराधिक मामले विचाराधीन हैं। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी करीब आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस पर टिप्पणी करने पर कई मामले चल रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 'चौकीदार चोर है' जैसी टिप्पणी करने पर वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट में बगैर शर्त माफी मांगी थी। राहुल गांधी ने इससे सीख लेने के बजाय अमर्यादित भाषा बोलना बंद नहीं किया। अदालत से बाहर भी राहुल ने इस तरह की अभद्रता करने पर अफसोस जाहिर नहीं किया। अब कांग्रेस इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाए हुए है। कांग्रेस इसे कर्नाटक चुनाव सहित आगामी चुनावों में मुद्दा बना रही है। इससे यही माना जाएगा कि कानून का सम्मान करने के बजाय आंखें दिखा कर सहानुभूति बटोरने के प्रयास से कांग्रेस देश में समस्याओं के असली मुद्दों से मुंह फेर रही है।

राहुल से पहले भी अभद्र टिप्पणी करने पर कई नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस की इंदौर इकाई के सेवादल के पूर्व जिलाध्यक्ष चन्द्रशेखर पटेल को पुलिस ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। नागपुर पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पूर्व कांग्रेस जिला पदाधिकारी शेख हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्डरिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुसैन ने पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्द कहे थे। इसी तरह के आरोप में लखनऊ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल से सम्बद्ध मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में कांग्रेस नेता कौस्तुभ बागची को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के कई मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। जिला या राज्यस्तरीय नेता होने के कारण इन मामलों में की हुई कानूनी कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय नहीं रही। परोक्ष तौर पर कांग्रेस के सर्वेसर्वा होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई की गूंज देशभर में है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने से भडक़ी कांग्रेस देश भर में धरने-प्रदर्शन करके इसे चुनावी मुद्दा बना रही है। सजा चूंकि अदालत से मिली है, इसलिए राहुल और कांग्रेस इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सके, किन्तु सजा से सदस्यता चली जाने के मुद्दे को लेकर मुद्दा बना लिया। विपक्षी दलों के नेता भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं ने अमर्यादित टिप्पणियों से बचने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। क्षेत्रीय दलों के नेताओं के एक-दूसरे के खिलाफ और भाजपा के नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने के कई मामले सामने आ चुके हैं।

> यह पहला मौका नहीं है जब किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को अदालत से मिली सजा और उसके बाद संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी हो। इससे पहले राजद के नेता लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता सहित कई नेताओं को विधानसभा और लोकसभा से सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। राहुल के सिवाय इन नेताओं को आपराधिक और दूसरे मामलों में जेल की सजा सुनाए जाने पर सदस्यता खोनी पड़ी।

देश में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की संख्या बढने के साथ ही सत्ता के लिए मची होड़ ने नैतिकता के साथ कानून की तमाम हदें भी पार की हैं। क्षेत्रीय दलों में ज्यादातार नेताओं के परिवार का बोलबाला है। इसीलिए सत्ता पाने की प्रतिस्पर्धा से राजनीति में गिरावट का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के पास अन्य दलों की तुलना में लोकसभा में सीटें बेशक कम हों, किन्तु विपक्षी दलों में कांग्रेस एकमात्र पार्टी है, जिसकी तीन राज्यों में सत्ता होने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का नेटवर्क है। इससे कांग्रेस की जिम्मेदारी अन्य दलों से कहीं ज्यादा है। सार्वजनिक जीवन में संयमित आचरण और ईमानदारी के मानदंड स्थापित करने की ज्यादा जिम्मेदारी भी कांग्रेस पर है। सत्ता पक्ष की नीतियों की आलोचना करना स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा और जरूरत है।

चिंतन विचार

मास्क में गुण बहुत हैं

प्रभात कुमार

कोरोनाजी ने फिर से डराना शुरू कर दिया है। वह या यह बात अलग है कि हम डरें या नहीं, मास्क पहनें या लटकाएं। सच तो यह है कि मास्क अब हमेशा की तरह सुरक्षा दिलाती लाठी की तरह हो गया है। समझदार लोगों ने फिर से कहना शुरू कर दिया है, मास्क में गुण बहुत हैं लगाते रहिए अंग। इतिहास गवाह है जब कोरोनाजी और ओमीक्रोनजी आए हुए थे तब भी मास्क खुश होकर तो नहीं लगाए जाते थे। शान के रखवाले बंदे खूब अदा से जुर्माना देते थे। यह भी सच है जिन्होंने मास्क अपनाया, स्वास्थ्य का स्वादिष्ट फल पाया। अब कोरोनाजी के रिश्तेदार डरा रहे हैं, इसलिए जुर्माना फिर से शुरू हो सकता है। तब महसूस होगा कि मास्क में सचमुच बहुत गुण हैं। विश्वगुरुओं के देश में हर आदमी तो वीआईपी हो नहीं सकता कि मास्क न लगाए और जुर्माना भी न दे, बीमार हो जाए तो मुफ्त में इलाज करवाए और अखबार में खबर विद रंगीन फोटो भी आए। कितना सकारात्मक है, मास्क लगाने से आप दूसरों के नुकसानदेह कीटाणु नहीं लेते और अपने कीटाणु चाह कर भी नहीं देते। मास्क थोडा बड़े आकार का हो तो आपके निजी फायदे बढ़ जाते हैं। आपका चेहरा, जैसा भी हो, पहचाना नहीं जाता। ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप बात नहीं करना चाहते, सामने से आ रहा हो, पास से निकलेगा, आप पहचान में नहीं आओगे। शर्त यह रहेगी कि आप अपना नाक भी ढक लें। किसी का उधार चुकाना है तो आपको तब तक मोहलत मिल जाती है जब तक आप बिना मास्क नहीं मिलते। अमुक विरोधी जिससे आपका शारीरिक पंगा भी हुआ था, बड़े साइज़ का मास्क आपको उससे बचाकर रख सकता है। इस सन्दर्भ में काला चश्मा और कैप नहीं, हैट अतिरिक्त सुरक्षा कवर प्रदान कर सकते हैं।

मास्क लगा हो तो सामने व्यक्ति को खुले मन से, चुपचाप बुरा भला कह सकते हैं। बड़बड़ाते हुए गाली जैसी चीज़ भी दे सकते हैं। आपकी भड़ास निकल जाएगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। चाहे आंखों से झूठी मुस्कुराहटें प्रेषित करते रहिए। मास्क देखकर वैसे भी कुछ इंच दूर तो रहेंगे ही। कभी ज्यादा गर्मी के कारण दम घुटने लगे तो थोड़ा किनारे होकर कुछ देर के लिए मास्क उतार कर पुनः पहन सकते हैं। नाक पर मास्क चढ़ा कर रखेंगे तभी नाक बचेगी। सिर्फ मुंह पर लटकाए रखने से अधर में लटक सकते हैं। महिलाओं ने तो मैचिंग मास्क फिर से निकाल लिए हैं। अब तो खराब न होने वाली लिपस्टिक मिल रही होगी। पारदर्शी मास्क तो आ ही गए थे। दुनिया किसी भी काम करने में लेट लतीफ हो, लेकिन ऐसे आविष्कार करने में चुस्त है। किसी नेता या अफसर से मिलना हो गया, वह आपके मास्क लगाने की तारीफ करेंगे, चाहे उन्होंने खुद न लगाया हो। दूसरों को बताएंगे कि हमारे यहां अभी तक कोविड प्रोटोकोल का पालन किया जा रहा है। वैसे भी सुरक्षा में बचाव को उचित माना गया है। बेचारे अनुशासन ने ज़िंदगी और इंसान को हमेशा बचाया है। मास्क रहेगा तो व्यक्ति फालतू बातें कुछ तो कम करेगा ही। उसे सोच समझकर बोलने की आदत पड़ सकती है जो उसके चरित्र निर्माण के लिए प्रशंसनीय रहेगी। यह बात मानने लायक है न कि मास्क में गुण बहुत हैं।

आ गईं बंपर छुट्टियां, इस महीने 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, दो लॉन्ग वीकेंड भी

परिवहन विशेष न्यूज

इस महीने यानी अप्रैल में बैंकों की जमकर छुट्टियां आ रही हैं। अलग-अलग जोन में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। साथ ही इस महीने दो लॉन्ग वीकेंड भी आ रहे हैं। पहला लॉन्ग वीकेंड 14,15 और 16 अप्रैल को है। वहीं, दूसरा लॉन्ग वीकेंड 21, 22 और 23 अप्रैल को है।

नई दिल्ली : वैसे तो अब अधिकतर बैकों से जुड़े काम ऑनलाइन ही हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बैंक खाता खुलवाने, चेक से जुड़े काम और ऐसे कई काम हैं, जिनके लिए बैंक ब्रांच जाने की जरूरत होती है। बैंक ब्रांच जाने से पहले आपको बैंकों की छुट्टियों (Bank Holidays in April 2023) के बारे में जरूर पता कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बैंक ब्रांच जाएं और बैंकों की छुट्टी हो। इस महीने यानी अप्रैल में अलग-अलग जोन में कुल 15 दिन बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। साथ ही इस महीने दो लॉन्ग वीकेंड (Long Weekend in April) भी आ रहे हैं। पहला लॉन्ग वीकेंड 14,15 और 16 अप्रैल को है। वहीं, दूसरा लॉन्ग वीकेंड 21, 22 और 23 अप्रैल को है। आरबीआई के नियम के अनुसार हर महीने के प्रत्येक रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार को बैंकों की छुट्टी रहती है। आइए जानते हैं कि इस महीने बैंक किन-किन तारीखों को बंद रहेंगे।

अप्रैल में कुल 15 दिन बंद रहेंगे बैंक

1 अप्रैल 2023 - इस दिन बैंक अकाउंट क्लोजिंग के चलते बैंकों में छुट्टी रहेगी।

2 अप्रैल 2023 - रविवार के चलते बैंकों का साप्ताहिक अवकाश होगा।

4 अप्रैल 2023 - महावीर जयंती के चलते अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर और रांची जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

5 अप्रैल 2023 - बाबू जगजीवन रान का जन्मदिन है। इस दिन तेलंगाना जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

7 अप्रैल 2023 - गुड फ्राइडे के चलते इस दिन आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, हैदराबाद, तेलंगाना, इंफाल, कानपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग और केरल जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

8 अप्रैल 2023 - दूसरे शनिवार के चलते बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

9 अप्रैल 2023 - रविवार के चलते बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

14 अप्रैल 2023 - अंबेडकर जयंती के चलते इस दिन अगरतला, अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, तेलंगाना, इंफाल, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्ची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, रांची, श्रीनगर और केरल में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

15 अप्रैल 2023 - बोहाग बिहू के चलते अगरतला, गुवाहाटी, कोच्ची, कोलकाता, शिमला और केरल जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

16 अप्रैल 2023 - रविवार के चलते बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

18 अप्रैल 2023 - शब ए कद्र के चलते जम्मू और श्रीनगर जोन में बैंक बंद रहेंगे।

21 अप्रैल 2023 - ईद के चलते अगरतला, जम्मू, कोच्ची, श्रीनगर और केरल में बैंक बंद रहेंगे।

22 अप्रैल 2023 - चौथा शनिवार होने से बैंक बंद रहेंगे।

23 अप्रैल 2023 - रविवार होने से बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

30 अप्रैल 2023 - रविवार होने से बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

पूर्व अटॉर्नी जनरल की पत्नी ने दिल्ली के पॉश इलाके में खरीदा आलीशान बंगला, कीमत और खासियत जानकर उड़ जाएंगे होश

दिल्ली का गोल्फ लिंक इलाका रहने के लिए अमीरों की पहली पसंद बना हुआ है। इस इलाके में घरों की सीमित उपलब्धता है। इस वजह से यह रहने के लिए अमीरों को काफी पसंद है। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की पत्नी ने इसी इलाके में 160 करोड़ का बंगला खरीदा है।

नई दिल्ली: भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल (Mukul Rohatgi) की पत्नी (Vasudha Rohatgi) ने दिल्ली के पॉश इलाके में एक आलीशान बंगला खरीदा है। यह बंगला चर्चा में बना हुआ है। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) की पत्नी वसुधा रोहतगी ने ये बंगला खरीदा है। इस बंगले की कीमत करीब 160 करोड़ रुपये बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बंगला गोल्फ लिंक्स इलाके में है। 2,160 स्क्वायर यार्ड में फैले इस आलीशान बंगले का प्लॉट एरिया 1806.35 स्क्वायर मीटर है, जबकि पूरी इमारत लगभग 1869.7 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करती है। रिपोर्ट के मुताबिक, रोहतगी परिवार (Mukul Rohatgi) ने इस बंगले के लिए 6.4 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी चुकाई और इससे जुड़ी रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस 24 फरवरी को पूरी हुई थी। बता दें कि पिछले साल भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने लुटियंस दिल्ली के सुंदर नगर में 85 करोड़ रुपये में 866 वर्ग गज का एक विशाल बंगला खरीदा था।

सुब्रमण्यम ने भी खरीदा था बंगला

सुब्रमण्यम ने उनसे पहले दिल्ली के सुंदर नगर इलाके में साल 2022 में 85 करोड़ रुपये का बंगला लिया था। रोहतगी (Mukul Rohatgi) साल 2014-17 के बीच 12वें अटॉर्नी जनरल रहे थे। मौजूदा समय में वह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। बीते दिनों डी मार्ट के संस्थापक राधाकिशन दमानी के परिवार के सदस्यों और सहयोगिरों ने मुंबई में बड़े पैमाने पर संपत्ति की खरीदारी की थी, जिसमें कुल 1238 करोड़ रुपये के मूल्य वाली 28 आवासीय इकाइयां खरीदी गई हैं।

काफी शानदार है बंगला

पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) की पत्नी वसुधा रोहतगी ने जो बंगला खरीदा है वो दिखने में काफी शानदार है। इस बंगले में सभी तरह की सुख-सुविधाएं मौजूद हैं। बंगले के आसपास काफी हरियाली है। इसका इंटीरियल काफी खास है। बंगले को काफी बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया गया है। बता दें कि घरों की सीमित उपलब्धता की वजह से दिल्ली का गोल्फ लिंक इलाका लोगों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। इस इलाके में ज्यादातर अमीर लोग रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से यहां की प्रॉपर्टी के रेट काफी ज्यादा हैं। हाल ही में कई कॉरपोरेट हस्तियों ने महंगे घर खरीदे हैं।

इनसाइड

मार्च में जीएसटी संग्रह 13% बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

नई दिल्ली। मार्च में जीएसटी संग्रह 13%बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। वित्त मंत्रालय ने रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है। मार्च 2023 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,60,122 करोड़ रुपये रहा। जिसमें सीजीएसटी 29,546 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 37,314 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 82,907 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र किए गए 42,503 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 10,355 करोड़ रुपये है। (माल के आयात पर एकत्र किए गए 960 करोड़ रुपये सहित)। चालू वित्त वर्ष में मार्च में चौथी बार जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। यह जीएसटी के लागू होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा संग्रहै। मार्च महीने में अब तक का सबसे अधिक आईजीएसटी संग्रह किया गया।

पिछले दो वित्तीय वर्षों में हुए जीएसटी संग्रह के आंकड़े

सीजीएसटी के लिए केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व 62,954 करोड़ रुपये रहा

सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी को 33,408 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 28,187 करोड़ रुपये का निपटान किया है। आईजीएसटी निपटान के बाद मार्च 2023 में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 62,954 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 65,501 करोड़ रुपये रहा।

पिछले वर्ष मार्च के मुकाबले जीएसटी संग्रह में 13% का हुआ इजाफा

मार्च 2023 का जीएसटी राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व की तुलना में 13% अधिक है। महीने के दौरान, माल के आयात से राजस्व पिछले साल की तुलना में 8% अधिक था और घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले साल के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से राजस्व की तुलना में 14% अधिक है। मार्च 2023 के दौरान रिटर्न फाइलिंग अब तक की सबसे अधिक रही है।

वर्ष 2022-23 में कुल सकल जीएसटी संग्रह 18.10 लाख करोड़ रुपये रहा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल सकल कर संग्रह 18.10 लाख करोड़ रुपये रहा। वहीं, पूरे वित्तीय वर्ष के लिए औसत सकल मासिक संग्रह 1.51 लाख करोड़ रुपये रहा। 2022-23 में सकल राजस्व पिछले साल की तुलना में 22% अधिक रहा। वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.55 लाख करोड़ रुपये रहा। जबकि पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में औसत मासिक संग्रह क्रमशः 1.51 लाख करोड़ रुपये, 1.46 लाख करोड़ रुपये और 1.49 लाख करोड़ रुपये रहा था।

क्या है दूध की इस महंगाई के पीछे वजह? अमूल के बाद अब दूसरी कंपनियां भी बढ़ा सकती हैं भाव

नई दिल्ली : घटती आमदनी और महंगाई से जूझ रहे लोगों को आज एक और मार पड़ी। दूध की कीमतें (Milk Price Hike) बढ़ा दी गईं। दूध की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में यूज होता है। दूध से बनी चाय से लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जिस घर में बच्चे हों, उसमें खाने से पहले दूध होना जरूरी हो जाता है। लेकिन अब दूध खरीदना इतना महंगा हो गया है कि गरीब परिवारों के लिए यह सोना बनता जा रहा है। खीर बनानी हो, तो सोचना पड़ जाता है। अमूल ने शनिवार को गुजरात में दूध की कीमतें (Amul Milk New Rate) बढ़ा दी हैं। अमूल ने कीमतें बढ़ाई हैं, तो जल्द ही मदर डेयरी (Mother Dairy) सहित दूसरी कंपनियां भी कीमतें बढ़ा सकती हैं।

अमूल ने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। कीमतों में यह इजाफा गुजरात में हुआ है। साथ ही कंपनी ने दूध की खरीद में पशुपालकों को 20 रुपये प्रति किलो फैट की दर से पैसा बढ़ाने का फैसला भी लिया है।

2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए दाम

अमूल ने गुजरात में ताजा दूध की कीमत (Amul Fresh Milk Price) एक अप्रैल से 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है। इस तरह एमआरपी में 3-4 फीसदी का इजाफा हो गया है। अमूल ने छह महीने में दूसरी बार दूध की कीमतें बढ़ाई हैं। अमूल के गोल्ड दूध सहित सभी कैटेगरीज में कीमतें बढ़ी हैं। पिछली बार अमूल ने जब दूध के भाव बढ़ाए थे, तब गुजरात में कीमतें नहीं बढ़ाई गई थीं। अब सिर्फ गुजरात में दूध के दाम बढ़ाए गए हैं।

कितने बढ़ गए भाव

गुजरात में शनिवार से अमूल गोल्ड के आधा लीटर दूध की कीमत (Amul Gold Milk Price) 32 रुपये हो गई है। अभी तक यह इसका भाव 31 रुपये था। वहीं, आधा लीटर में अमूल शक्ति दूध की नई कीमत 29 रुपये, अमूल काउ मिल्क की 27 रुपये, अमूल ताजा 26 रुपये, अमूल स्लिम एंड ट्रिम दूध 25 रुपये हो गई है। हालांकि, दिल्ली में अमूल दूध की कीमतें इससे अधिक हैं।

क्यों बढ़ रहे दाम

दूध की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे के पीछे कारण है चारे की महंगाई। चारा लगातार महंगा हो रहा है। कंपनी का कहना है कि बीते कुछ महीने से दूध की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हो रही है। यह चारे के कारण है। जानवरों के चारे की कीमतों में 13 से 14 फीसदी का उछाल आया है। इससे किसानों की लागत बढ़ रही है

अब गुजरात में यह है अमूल दूध का भाव

दूध (500 ml) (रुपये)	कीमत
अमूल गोल्ड	32
अमूल शक्ति	29
अमूल काउ मिल्क	27
अमूल फ्रेश	26
अमूल स्लिम एंट ट्रिम	25

किसानों को मिलेगा ज्यादा दाम

अमूल ने ग्राहकों के लिए तो दूध के दाम बढ़ाए, लेकिन साथ ही उसने किसानों को फायदा भी पहुंचाया है। अमूल ने दूध की खरीद में पशुपालकों को 20 रुपये प्रति किलो फैट की दर से पैसा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस तरह अब पशुपालकों को ज्यादा पैसा मिलेगा। उन्हें 800 रुपये की बजाय 820 रुपये प्रति किलो फैट का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा दूध भरने वाले लोगों को दुर्घटना बीमा देने की घोषणा भी दी है।

गजब का शेयर! लगाए थे ₹1 लाख मिले पूरे ₹2 करोड़, 4 रुपये का स्टॉक पहुंचा सीधे ₹900 के पार

शेयर बाजार में करोड़पति बनाने वाले बहुत से स्टॉक हैं। ऐसा ही एक शेयर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का भी है। इस शेयर ने लॉन्ग टर्म के साथ शॉर्ट टर्म में भी निवेशकों को मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयरों में अभी भी बंपर तेजी देखने को मिल रही है।

नई दिल्ली: शेयर बाजार में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने निवेशकों को एक झटके में करोड़पति बना दिया है। ऐसा ही एक शेयर गोदरेज ग्रुप की कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी (Godrej Consumer Products Limited) का है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Godrej Consumer Products Limited) ने अपने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। इस शेयर में एक लाख रुपये का निवेश करने वाले करोड़पति हो गए हैं। गोदरेज ग्रुप की इस कंपनी के शेयर में अभी भी बंपर तेजी बनी हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस शेयर में अभी और तेजी आ सकती है। बीते शुक्रवार को गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 968.05 रुपये के स्तर पर बढ़त के साथ बंद हुए थे। शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आप किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहाकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इस तरह निवेशकों को बनाया करोड़पति

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Godrej Consumer Products Limited) के शेयरों ने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को मालामाल किया है। 22 जून 2001 को गोदरेज कंपनी के शेयर 4 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहे थे। वहीं अभी कंपनी के शेयर 968 रुपये के स्तर पर बने हुए हैं। ऐसे में देखें तो पिछले 22 साल में यह शेयर 23 हजार फीसदी से ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में अगर देखें तो अगर किसी निवेशक ने साल 2001 में इस शेयर में एक लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी रकम बढ़कर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी होती।

शॉर्ट टर्म में भी किया मालामाल

ऐसा नहीं है कि इस शेयर ने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में ही मालामाल किया हो। शार्ट टर्म में भी स्टॉक ने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। बीते साल 30 मार्च को ये शेयर करीब 700 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इस हिसाब से देखें तो एक साल में स्टॉक ने निवेशकों को 39 फीसदी का रिटर्न दिया है। जानकारों के मुताबिक, आने वाले समय में शेयर में और उछाल देखने को मिल सकता है।

नकदी संकट से जूझ रहे 'पड़ोस' में महंगाई से हालात हो सकते हैं और बदतर, सरकार ने जताई आशंका

वित्त मंत्रालय के एक रूढ़िवादी आंतरिक आकलन ने मार्च में मुद्रास्फीति की दर लगभग 34 प्रतिशत बताई। मंत्रालय ने कहा कि बढ़ती कीमतों का एक संभावित कारण राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) कार्यक्रम से 1.1 अरब डॉलर के वित्तपोषण की खेप को अंतिम रूप देने में देरी से आर्थिक संकट और बढ़ रहा है।

नई दिल्ली। नकदी संकट से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक संकट के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी को जिम्मेदार ठहराते हुए अर्थव्यवस्था में नरमी के साथ-साथ अधिक मुद्रास्फीति की चेतावनी दी है। एक पाकिस्तानी अखबार के अनुसार वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी अपनी मासिक परिदृश्य रिपोर्ट में यह भी कहा कि राजनीतिक अस्थिरता देश को और अधिक मुद्रास्फीति की ओर ले जा रही है।

पड़ोसी देश में पिछले महीने के लिए अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान के आंकड़े को रोकते हुए वहां के वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था के निराशाजनक दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए कहा कि मासिक आर्थिक संकेतक, जो पिछले और वर्तमान संकेतकों के आधार पर आर्थिक विकास दर की भविष्यवाणी करने का माध्यम है वह धीमा हो गया है।

मंत्रालय ने कहा, 'मार्च में मुद्रास्फीति ऊपरी स्तर पर रह सकती है जैसा कि फरवरी में देखा गया था। उस समय यह 31.5 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि इस बार कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन बाजार को उम्मीद है कि कई नकारात्मक कदम उठाये जाने के कारण मुद्रास्फीति 36 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

वित्त मंत्रालय के आकलन के मुताबिक पाक में महंगाई दर 33 प्रतिशत

वित्त मंत्रालय के एक रूढ़िवादी आंतरिक आकलन ने मार्च में मुद्रास्फीति की दर लगभग 34 प्रतिशत बताई। मंत्रालय ने कहा कि बढ़ती कीमतों का एक संभावित कारण राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) कार्यक्रम से 1.1 अरब डॉलर के वित्तपोषण की खेप को अंतिम रूप देने में देरी से आर्थिक संकट और बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'स्थिरीकरण कार्यक्रम में देरी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट ने आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ा दिया है, जिसके कारण मुद्रास्फीति की आशंका मजबूत बनी हुई है।

आईएमएफ से बेलआउट पैकेज हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान 6.5 अरब डॉलर के आईएमएफ बेलआउट पैकेज को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, जिसे वाशिंगटन स्थित वैश्विक ऋणदाता ने 2019 में मंजूरी दी थी। हालांकि, इस बीच पेट्रोल सब्सिडी और वाणिज्यिक बैंकों से सीधे उधार लेने के प्रयासों जैसे इसके गलत कदमों ने नकदी की कमी वाले देश के लिए मामलों को और जटिल बना दिया है।

पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) की संकुचनकारी मौद्रिक नीतियां भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद नहीं कर रही हैं। एसबीपी ने इस महीने हुई पिछली मौद्रिक नीति के फैसले में नीतिगत दर को तीन प्रतिशत बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया था।

असम सरकार ने 4 प्रतिशत बढ़ाया सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, 42 प्रतिशत तक पहुंचा

गुवाहटी। असम सरकार ने राज्य सेवा कर्मचारियों को सौगात दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एलान किया है कि उनकी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इसके अलावा उन्होंने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ा दिया है, जो अब 42% हो गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर लिखा कि हमारी सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए काम करने वाली सरकार है। मुझे एलान करते हुए खुशी हो रही है कि हम राज्य कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा रहे हैं। बता दें, कर्मचारियों का महंगाई पहले 38 प्रतिशत था, जो अब 4 प्रतिशत तक बढ़ने के बाद 42 प्रतिशत हो गया है।

रेशम उत्पादों के लिए सीएम ने कही यह बात

सीएम सरमा ने कहा कि वैश्विक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मुगा और एरी जैसे असम रेशम उत्पादों की सूची तैयार करने के लिए शीर्ष डिजाइनरों से सलाह ली जानी चाहिए। उन्होंने राज्य के लोगों से आने वाले रोंगाली बिहू के दौरान कम से कम एक हथकरघा गमोसा (पारंपरिक दुपट्टा या तौलिया) खरीदने का आग्रह किया। रोंगाली बिहू राज्य में बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल के मध्य में असमिया नए साल के रूप में मनाया जाता है।

एटी रामास्वामी ने थामा भाजपा का दामन, अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में ग्रहण की सदस्यता

नई दिल्ली। कर्नाटक के अरकलगुडा से वरिष्ठ विधायक एटी रामास्वामी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। रामास्वामी ने जनता दल (सेक्यूलर) के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था। उन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री और एटी रामास्वामी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। भाजपा में शामिल होने के बाद रामास्वामी ने कहा कि मैं वास्तव में भाजपा के काम करने के तरीके से प्रभावित हूं। मैं पैसे की ताकत का शिकार हूं, क्योंकि मैं हमेशा अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की बात करता था। मैं बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। मैं सिर्फ लोगों की सेवा करने का अवसर चाहता हूं।

12 राज्यों में सुरक्षा बलों के 49 हजार करोड़ रुपये फंसे

अकेले CRPF के 44000 करोड़ बकाया, ऐसे होगी वसूली

राज्यसभा में पेश हुई गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की 242वीं रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि गोवा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, नगालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर ने अभी तक अपना तय भुगतान नहीं किया है...

नई दिल्ली। जब कभी किसी राज्य में दंगा, चुनाव या अन्य कोई ऐसी गतिविधि होती है, जिसमें कानून व्यवस्था के बिगड़ने का अंदेशा बना रहता है, तो वहां पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों 'सीएपीएफ' की तैनाती की मांग की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी बिना कोई देरी किए 'सीएपीएफ' को संबंधित राज्य के लिए रवाना कर देता है। हालांकि इस तरह के अधिकांश टॉस्क 'सीआरपीएफ' द्वारा पूरे किए जाते हैं। अब राज्यों की ओर केंद्रीय सुरक्षा बलों के 49 हजार करोड़ रुपये फंस गए हैं। मतलब, इतनी राशि बकाया है। इसमें अकेले सीआरपीएफ के ही 44083.51 करोड़ रुपये हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दर्जनभर राज्यों से कई बार आग्रह किया है कि इस राशि का भुगतान किया जाए, लेकिन राज्यों ने इतनी बड़ी राशि लौटाने की बजाए, उसे माफ करने की बात कह दी। केंद्र सरकार अब इस बकाया राशि का भुगतान कराने के लिए सख्त कदम उठा सकती है।

इन 12 राज्यों की तरफ बकाया हैं 49912.37 करोड़ रुपये

राज्यसभा में पेश हुई गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की 242वीं रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद बृजलाल, गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि विभिन्न राज्यों की तरफ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 49912.37 करोड़ रुपये बकाया हैं। जिन राज्यों ने अभी तक अपना तय भुगतान नहीं किया है, उनमें गोवा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, नगालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। संसदीय समिति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा था कि इस बकाया राशि के भुगतान के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। मंत्रालय का जवाब था कि इस संबंध में नियमित आग्रह किया जा रहा है। प्रत्येक तीन माह में इस तरह का आग्रह किया जाता है।

मासिक स्तर पर उठाया जाए यह मुद्दा

गृह मंत्रालय ने संसदीय समिति को सूचित किया कि इन राज्यों ने उक्त राशि को माफ करने के लिए प्रार्थना दी है। समिति ने मंत्रालय से कहा है कि इसे लेकर कठोरता से बात की जाए। उक्त राशि के भुगतान के लिए राज्यों के साथ प्रमुखता से इस विषय को उठाया जाए। इतना ही नहीं, समिति ने मासिक स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। भारत सरकार को भी इस विषय में गंभीरता से प्रयास करने चाहिए, ताकि समयबद्ध तरीके से 49912.37 करोड़ रुपये का भुगतान संभव हो सके। आंतरिक ड्यूटी में सीआरपीएफ की बेहतरीन भूमिका, इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार इस बल की सराहना कर चुके हैं।

दंगे/चुनाव में होती है सीआरपीएफ की मांग

2021 में पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ कैंप में पहुंचे गृह मंत्री शाह ने कहा था कि देश में कहीं भी चुनाव या दंगे होते हैं तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री मांग करते हैं कि उन्हें सीआरपीएफ के जवान उपलब्ध कराए जाएं। पिछले सप्ताह छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर आयोजित परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए अमित शाह ने कहा, मैं किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहता हूं और तभी किसी अप्रिय घटना का समाचार आता है, मगर साथ में जब यह बात भी पता चलती है कि सीआरपीएफ वहां पहुंच गई है तो मैं निश्चिंत होकर आगे का कार्यक्रम चालू रखता हूं। मुझे भरोसा है कि गलत मंसूबे वाले लोगों को नसीहत करे बगैर सीआरपीएफ जवान वापस नहीं लौटता।

राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने आया नया संकट

आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में बिसात बिछ चुकी है। कांग्रेस और भाजपा के साथ अन्य दल भी चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण को लेकर प्रदेश कांग्रेस टेंशन में है। टेंशन यह है कि उन 19 विधानसभा सीटों पर किसे टिकट दे, कांग्रेसी नेताओं को दें या उन्हें जिन्होंने जुलाई 2020 में सरकार को गिरने से बचाया था। इन 19 विधानसभा सीटों में 13 वो सीटें हैं जहां कांग्रेसी प्रत्याशियों को हराते हुए निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। इन 13 निर्दलीय विधायकों ने सरकार को समर्थन दे दिया। साथ ही सियासी संकट के दौरान सरकार को बचाने में मदद की। ऐसे में अब आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट वितरण को लेकर सियासी भंवर में फंसी हुई है।

'मैं मौत से डरता नहीं...' पटियाला जेल से बाहर आते ही नवजोत सिंह सिद्धू का पहला बयान, 10 महीने से थे कैद

रोड रेज मामले में 10 महीने से कैद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को जेल से रिहा कर दिया गया है। बाहर आते ही सिद्धू का आक्रामक रुख नजर आया। उन्होंने पंजाब सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह मौत से डरते नहीं हैं।

पटियाला: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल से रिहा हो गए हैं। रोड रेज मामले में वह पिछले 10 महीने से जेल में बंद थे। जेल से बाहर आते हुए सिद्धू ने समर्थकों को देखकर हाथ हिलाया और जमीन के पैर छुए। गौरतलब है कि सुबह से ही सिद्धू की रिहाई को लेकर चर्चा थी जिसके चलते मीडिया और उनके समर्थक जेल के बाहर इकट्ठा थे।

जेल से बाहर आते वक्त सिद्धू ने नेवी ब्लू पगड़ी और कुर्ता पहना हुआ था जबकि आसमानी रंग की जैकेट पहनी थी। सिद्धू ने जेल से बाहर आते ही कहा, 'यहां अब लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं बची है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश हो रही है। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप पंजाब को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद कमजोर पड़ जाएंगे।'

सिद्धू ने कहा, 'मुझे दोपहर के आसपास रिहा किया जाना था लेकिन उन्होंने इसमें देरी की। वे चाहते थे कि मीडिया के लोग चले जाएं। इस देश में जब भी कोई तानाशाही आई है तो एक क्रांति भी आई है और इस बार उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी। वह सरकार को हिला देंगे।'

सिद्धू ने कहा, 'संविधान को मैं अपना ग्रंथ मानता हूं, तानाशाही हो रही है। जो संस्थाएं संविधान की ताकत थी, वही संस्थाएं आज गुलाम बन गई हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मैं मौत से डरता नहीं हूं क्योंकि मैं जो करता हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं।'

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल से रिहा, 10 महीने बाद आए बाहर

नवजोत सिद्धू की गैरमौजूदगी में उनकी टीम द्वारा संचालित अकाउंट से शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा गया था कि सभी को सूचित किया जाता है कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को कल पटियाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा।

चंडीगढ़: कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल से रिहा हो गए। 1988 के रोडरेज के मामले में 59 साल के सिद्धू एक साल जेल की सजा काट रहे थे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने पटियाला की एक अदालत में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उन्हें पिछले साल 20 मई को जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अपर्याप्त सजा देने के लिए दिखाई गई कोई भी सहानुभूति न्याय प्रणाली को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी। इससे कानून के प्रभाव के प्रति जनता के भरोसे पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस घटना में 65 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी।

नवजोत सिंह सिद्धू की र हिाई में हो रही देरी

पंजाब के पटियाला जेल के बाहर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बेटे करण सिद्धू ने बताया कि अभी कुछ औपचारिकताएं की जा रही हैं। मुझे संदेह है कि वे (जेल प्रशासन) यहां मीडिया और भीड़ की मौजूदगी के कारण उनकी (नवजोत सिंह सिद्धू) रिहाई में देरी कर रहे हैं। जेल अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि उन्हें आज रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि उन्हें दोपहर में रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अब देर हो चुकी है।

नवजोत सिंह के बेटे ने कही ये बात

नवजोत सिंह के बेटे करण सिद्धू ने कहा कि परिवार नवजोत सिंह सिद्धू के साथ प्राईवेट समय बिताना चाहते है। परिवार के लिए पिछला एक साल बेहद मुश्किलों भरा रहा। डॉक्टर नवजोत कौर को कैंसर हो गया था, उनकी सर्जरी हुई है। भविष्य को लेकर पिता जी ने काफी आत्म मंथन किया है। उनका कांग्रेस में क्या रोल रहेगा यह पार्टी तय करेगी।

सिद्धू को क्या भूमिका सौंपेगी कांग्रेस

सिद्धू की रिहाई से कांग्रेस की पंजाब इकाई का मनोबल बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस जेल से रिहाई के बाद सिद्धू को क्या भूमिका सौंपेगी। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने हाल में कहा था कि वह स्टेज दो के कैंसर से पीड़ित हैं। उन्होंने भी शुक्रवार को एक भावनात्मक ट्वीट किया था। सिद्धू की पत्नी ने कहा कि पंजाब के लिए नवजोत का प्यार हद से ज्यादा है।

पूरी दुनिया में आने वाला है गेहूं का बड़ा संकट! रूस शुरू कर सकता है नए तरह का युद्ध

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: दुश्मन को चित करने और अपनी ताकत दिखाने के लिए आज तोप, टैंक, मिसाइल, लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, युद्धपोत वगैरह ही हथियार नहीं हैं। अनाज भी एक बड़ा हथियार है। खाद्यान्न आज जियोपॉलिटिक्स का बड़ा औजार है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को अब गेहूं का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसकी आंच पूरी दुनिया महसूस करेगी। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है। रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले से ही ग्लोबल फुड सप्लाई गड़बड़ाई हुई है। पिछले साल खाद्यान्न की कीमतें तेजी से बढ़ी थीं और अब रूस जिस तरह गेहूं निर्यात पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा रहा है, उससे स्थिति और खराब होगी। रूस की कोशिश है कि गेहूं निर्यात में सिर्फ सरकारी कंपनियां या फिर उसकी घरेलू कंपनियां ही रहें ताकि वह एक्सपोर्ट को हथियार की तरह और ज्यादा कारगर इस्तेमाल कर सके। इस बीच दो बड़े इंटरनैशनल ट्रेडर्स एक्सपोर्ट के लिए रूस में गेहूं खरीद को रोकने जा रहे हैं जिसके बाद ग्लोबल फुड सप्लाई पर रूस की पकड़ और मजबूत हो जाएगी।

दो बड़े इंटरनैशनल ट्रेडर्स से रूस से निकलने का किया ऐलान

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Cargill Inc और Viterra ने रूस से गेहूं का निर्यात बंद करने का ऐलान किया है। इन दोनों की पिछले सीजन में रूस के कुल खाद्यान्न निर्यात में 14 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। इनके जाने से दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक रूस का ग्लोबल फुड सप्लाई पर शिकंजा और मजबूत होगा। इनके अलावा आर्कर-डेनिएल्स मिडलैंड कंपनी भी रूस भी अपना कारोबार समेटने पर विचार कर रही है। लुइस ड्रेयफस भी रूस में अपनी गतिविधियों को कम करने पर विचार कर रही है। गेहूं का नया सीजन शुरू हो चुका है। 15 मई से रूस गेहूं की नई पैदावार का निर्यात शुरू कर देगा। अब इंटरनैशनल ट्रेडर्स के पीछे हटने से रूसी गेहूं निर्यात पर सरकारी और घरेलू कंपनियों का ही दबदबा होगा। वह और प्रभावी ढंग से इसका इस्तेमाल जियोपॉलिटिक्स के लिए कर सकेगा। वह कीमतों को भी प्रभावित करने की स्थिति में होगा। मध्य पूर्व और अफ्रीकी देश रूसी गेहूं के बड़े खरीदार हैं।

गेहूं निर्यात का हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है रूस

रूस अब गेहूं निर्यात के लिए गवर्नमेंट टु गवर्नमेंट डील पर जोर दे रहा है। सरकारी कंपनी OZK पहले ही तुर्की के साथ गेहूं बिक्री के कई समझौते कर चुकी है। उसने पिछले साल कहा था कि वह इंटरनैशनल ट्रेडर्स से छुटकारा पाना चाहती है और सीधे देशों को निर्यात करने की दिशा में काम कर रही है। रूस गेहूं का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद के चुनिंदा देशों को ही उसका निर्यात करेगा। इससे फुड सप्लाई चेन तो प्रभावित होगी ही, पिछले साल की तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी भी हो सकती है।

रूस के गेहूं वाले हथियार की दुनिया पर पड़ सकती है आंच

रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से पिछले साल दुनियाभर में गेहूं और आटे की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ था। कई देश खाद्य संकट के मुहाने पर खड़े हो गए तो कई जगह खाने-पीने की वस्तुओं की महंगाई चरम पर पहुंच गई। पिछले साल भारत में भी गेहूं और आटे की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी जिसके बाद सरकार ने गेहूं निर्यात रोक दिया था। भारत खुद बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है लेकिन जो देश खाद्यान्न की जरूरतों के लिए बहुत हद तक आयात पर निर्भर हैं, वह बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। दुनिया में एक बार फिर गेहूं और आटे की कीमतें तेजी से बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है।

फुड वॉर दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं

खाद्यान्न का हथियार के तौर पर इस्तेमाल दुनिया के लिए अच्छा संकेत तो बिल्कुल नहीं है। फुड वॉर की पहली बार 2007 में तब झलक दिखी थी जब सूखा, प्राकृतिक आपदा जैसी वजहों से दुनियाभर में खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ था। तब रूस, अर्जेंटिना जैसे अहम खाद्यान्न निर्यातक देशों ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 2008 में महीनों तक खाद्यान्न के एक्सपोर्ट पर एक तरह से रोक दिया था। इसकी वजह से दुनिया में तमाम जगहों पर राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट पैदा हुआ था। संयोग से तब वैश्विक मंदी भी आई थी जिसकी वजहों में फुड वॉर को भी गिना जा सकता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959.
किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय में ही होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये मसौदे के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023